General Discussion on Union Budget (2024-25) ? and Union Territory of Jammu and Kashmir Budget (2024-25)-and Demands for Grants (Union Territory ofJammu and Kashmir), 2024-25?Contd.

माननीय सभापति: बजट पर सामान्य चर्चा ।

श्री जुगल किशोर शर्मा जी

श्री जुगल किशोर (जम्मू): आदरणीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से इस गरिमामयी सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जिनके सहयोग से नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को तीसरी बार बनाने का मौका दिया है । इतिहास बना है क्योंकि पिछले 60 वर्षों में ही ऐसा हुआ । अगर किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में देश में तीसरी बार किसी ने सरकार बनाई है तो वह हैं, देश के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र भाई मोदी । यह तब संभव हो पाया जब देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले दस वर्षों में देश की सेवा की और ऐसी योजनाएं देश को समर्पित कीं और इनका लाभ देश के गरीबों और गांवों के किसानों ने लिया । तीसरी बार वही व्यक्ति प्रधान मंत्री बन सकता है जिसने देश और समाज के हित में काम किया हो । जनता सब जानती है कि किसको कहां बिठाना है और जनता ने जिसे जहां बिठाना था, वहां बिठा दिया और अब यह दिख भी रहा है । बड़े लोभ-लुभावने नारे दिए गए और झूठ का सहारा लेकर देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया गया । मैं देश की जनता का आभारी हूं कि जनता ने झूठ का सहारा न लेते हुए देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और एनडीए पर विश्वास जताते हुए तीसरी बार माननीय नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाया ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, जो खड़े हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । आप लोग भी बैठ जाएं । मैं सभी के लिए कह रहा हूं ।

? (व्यवधान)

श्री जुगल किशोर: मैं इस गरिमामयी सदन के समक्ष माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024-25 के वित्तीय बजट पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं और इसका समर्थन भी करता हूं ।

मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने सभी प्रमुख बातों को ध्यान में रखते हुए सातवीं बार सदन के समक्ष वित्तीय बजट प्रस्तुत किया । यह बजट सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । इसके द्वारा सरकार की लोगों के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही का पता चलता है ।

महोदय, यह बजट विकसित भारत बनाने में कारगर और उपयोगी सिद्ध होगा वित्तीय बजट में बहुत-सी ऐसी बातों का ध्यान रखा गया ताकि देश के हर एक नागरिक को इसका फायदा मिल सके । मैं विस्तार में न जाते हुए कुछ खास बातों की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस बजट में कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान दिया गया है और भरपूर अवसरों का सृजन करने के लिए नौ प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना भी की गई है । इस बजट में कृषि में उत्पाकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, अवसंरचना और गांव, गरीबों तथा किसानों की चिंता की गई है ।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सहकारिता नीति, सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है । रोजगार संबंधी प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया गया है । कौशल प्रशिक्षण प्रधान मंत्री पैकेज के अंतर्गत चौथी योजना के रूप में राज्य सरकारों और उद्योगों के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित कई नई योजनाएं बनाई जाएंगी । यह बेहद खुशी की बात है कि पांच वर्ष की अवधि में कई लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा । वहां कौशल प्रशिक्षण ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाई कराई गई है ।

महोदय, जम्मू-कश्मीर का बजट भी पेश किया गया है और यहां उस पर चर्चा हो रही है । जम्मू-कश्मीर का जो बजट है, वह जम्मू-कश्मीर की बेहतरी और जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए है, जो यहां पर स्पष्ट दिखाई देता है । इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा क्षेत्र, खेल एवं युवा पहलें, कौशल विकास आदि, हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए जम्मू-कश्मीर के बजट में बात रखी गई है और उसके लिए फंड्स उपलब्ध करवाए गए हैं ।

महोदय, केंद्र में अगर मैं जम्मू-कश्मीर की बात करूं तो केंद्र में जबसे नेरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और अनुच्छेद 370 तथा 35 ए को हटाया गया है, तभी से जम्मू-कश्मीर बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है । जम्मू-कश्मीर में विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है । अगर मैं कहूं तो जम्मू-कश्मीर में विकास 100 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है । जैसे ही आप लखनपुर से जम्मू-कश्मीर की ओर बढ़ेंगे तो आपको बदलता हुआ जम्मू-कश्मीर दिखाई देगा और बदलता जम्मू भी । आपको विकास के कार्य हर जगह दिखाई देंगे ।

महोदय, आज जम्मू-कश्मीर में बहुत बड़े-बड़े फ्लाई ओवर, ब्रिज और नेशनल हाइवेज बन रहे हैं । एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली, अमृतसर और कटरा तक जा रहा है, उसका काम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है । मैं अगर जम्मू के विकास की बात करूं तो जम्मू की हमेशा उपेक्षा होती रही है, चाहे वह कांग्रेस के नेतृत्व में हो, नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व में हो या पीडीपी के नेतृत्व में हो । विशेष तौर पर जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू-कश्मीर के समाज के हित के लिए और जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए पहले कोई कदम नहीं उठाये जाते थे । सिर्फ पार्टी और परिवार की चिंता करना ही पार्टियों के स्वभाव में था ।

आज की डेट में जम्मू में और जम्मू-कश्मीर में झेलम, जो हमारी झील है, उसकी साफ-सफाई और सुन्दरता के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है । जम्मू में अभी रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है । गुजरात की साबरमती नदी की तर्ज पर जम्मू में भी कश्मीर घाटी की तरह एक झील का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है । जम्मू जू और बाघा बॉर्डर की तर्ज पर सुचेतगढ़ में एक परेड का आयोजन किया जाता है । रोपवे, रोड और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं ।

महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं । देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जम्मू में एम्स दिया है । मुझे लगता है कि एम्स की वे सारी सुविधाएं, जो देश भर में होती हैं और विशेष तौर पर दिल्ली एम्स में जो होती हैं, उससे भी बढ़कर नई टेक्नोलॉजी के तहत नई-नई मशीनें जम्मू एम्स में लगवाई जा रही हैं ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त, 2019 के बाद जब अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाया गया था, उसके बाद अभी 2024 में जो लोक सभा का चुनाव हुआ है, वह जम्मू-कश्मीर में पहला चुनाव था । मैं कहना चाहता हूं कि यह पहली बार हुआ कि 30 वर्षों में घाटी में भी 60 परसेंट के करीब लोग वोट डालने बाहर निकले थे । उन्होंने लोकतंत्र को जिताया है । कश्मीर घाटी में भी लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था और वोटिंग हुई थी । यह लोकतंत्र की जीत तो है ही, लेकिन यह राष्ट्रीय नीतियों के प्रति समर्थन भी दिखाता है । ? (व्यवधान)

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदायों का विकास, महिला कल्याण, सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार और अनुकूल सुरक्षा परिदृश्य के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है । ताकि दोनों सरकारों द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं और परियोजनाओं को वांछित परिणाम के साथ धरातल पर उतारा जा सके ।

महोदय, इसने जम्मू-कश्मीर के लगभग सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका नभाई है । मैं कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 हटने एवं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के पारित होने के बाद ही सभी केन्द्रीय कानून जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र पर लागू हो गए हैं । उससे वहां के लोगों में अति खुशी की भावना है, जिससे वहां के लोग कई वर्षों से वंचित थे । अब भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में पूरी तरह से लागू है । जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा चलाया गया अभियान अब पूरा हुआ है । ?एक राष्ट्र, एक निशान, एक विधान?, अब जम्मू-कश्मीर में लागू हुआ है ।

महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि चुनाव तो वहां पहले भी हुआ करते थे, लेकिन लोगों की रुचि चुनावों में नहीं हुआ करती थी । अब नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र में जो एनडीए की सरकार बनी है, उनके द्वारा जम्मू-कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, अब किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है । जम्मू-कश्मीर में बराबर विकास हो रहा है । इसी के साथ ही साथ केन्द्र सरकार ने और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं । अब आरक्षण का लाभ भी लोगों को मिल रहा है ।

महोदय, मैं कहना चहता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लाभ को 8 प्रतिशत बढ़ाया गया है । अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एलओसी के निवासियों को पहले तीन प्रतिशत आरक्षण मिलता था, लेकिन अब उसको चार प्रतिशत कर दिया गया है । पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ और उनकी आय सीमा को 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक कर दिया गया है । अब पहाड़ में रहने वालों (पहाड़ियों) को भी आरक्षण मिल रहा है । वे कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे ।

महोदय, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम पारित होने के बाद जम्मू-कश्मीर अपनी बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहा है । जम्मू-कश्मीर में कई सारे कदम उठाए गए हैं । पहले जो जम्मू-कश्मीर कमजोर दिखाई देता था, आज एक सशक्त जम्मू-कश्मीर बनने जा रहा है । जम्मू-कश्मीर में अमन और शांति भी बहाल हो रही है । जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में वाल्मीकि शब्द को शामिल करने का जो प्रावधान रखा गया था, उससे भी वहां के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला है ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई । उसने हमेशा स्वार्थ की राजनीति की है । पार्टी और परिवार की राजनीति की है । उन्होंने समाज और देश की चिंता न करते हुए जम्मू-कश्मीर को कभी आगे नहीं बढ़ाया । मैं बताना चाहता हूं कि जब जम्मू-कश्मीर के दो टुकड़े हुए थे, वह कांग्रेस पार्टी की स्वार्थ की राजनीति की वजह से हुए थे । मुझे मालूम है कि यहां पर क्या-क्या बोला गया है ।

महोदय, मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां बहुत कुछ दिया गया है और इस बजट में भी बहुत कुछ दिया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू पर्यटन उद्योग केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए जीवनरेखा है, जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है । जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद बदलते माहौल एवं अनुच्छेद 370 और 35(ए) हटने के बाद वर्ष 2023 में जम्मू-कश्मीर में 2.11 करोड़ पर्यटकों का रिकॉर्ड आगमन हुआ है । इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था । यह ऐतिहासिक है ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जून माह के अंत तक 1,00,02,000 पर्यटक जम्मू-कश्मीर में सैर-सपाटा करने गए हैं । वे जम्मू-कश्मीर को देखने गए हैं । वे बदलते हुए जम्मू-कश्मीर का आनंद लेने के लिए वहां पहुंचे हैं । इस बजट में जम्मू-कश्मीर की बेहतरी के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं । मैं यहां पर उन सबका जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहां पर कुछ खास बिंदुओं पर जरूर अपनी बात रखूंगा ।

13.00 hrs

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इसी बजट में कहा गया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बहुत सारी सड़कें बनी हैं और उनके साथ-साथ 7,886 किलोमीटर की सड़कें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बनी हैं, जो रिकॉर्ड है । ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था । एक 58 किलोमीटर का रिंग रोड़ बनकर तैयार हो गया है । वह बहुत सुंदर है । मैं चाहूंगा कि लोग उसको देखने वहां पर आएं । अगर मैं रेल की बात करूं तो उसमें सारी अच्छी-अच्छी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं । मैं एक बात और कहता हूं कि अगर रेल का सबसे ऊंचा ब्रिज कहीं बना है तो वह जम्मू कश्मीर में बना है और रियासी कोडी में बना हुआ है ।

महोदय, वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक 1,044 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन वर्ष 2024-25 में ही 3,694 करोड़ रुपये रेलवे की तरफ से वहां पर खर्च किये जा रहे हैं । वर्ष 2014 से 2024 तक 87 किलोमीटर का नया ट्रैक बनाया जा रहा है । वहां 343 किलोमीटर लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है । ?अमृत स्टेशन योजना? के माध्यम से चार रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है । जम्मूतवी, बडगाम, माता वैष्णो देवी कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशनों का जोर-शोर से विकास कार्य चल रहा है । अगर मैं ?जल जीवन मिशन? की बात करूं तो ?जल जीवन मिशन? जम्मू कश्मीर के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है । वैसे तो पूरे देश में ?जल जीवन मिशन? के माध्यम से जो कार्य चल रहे हैं, वे वरदान सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी ?जल जीवन मिशन? के माध्यम से हो रहे कार्य वरदान सिद्ध हो रहे हैं । हर घर नल और नल में जल के माध्यम से लोगों को जल पहुंचाया जा रहा है ।

महोदय, स्मार्ट सिटी, कृषि क्षेत्र में सुधार और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में तीन हजार डेयरी नई खोली जाएंगी । इससे लोगों को रोजगार मिलेगा । सोलर के माध्यम से छतों पर बिजली बनेगी । उसका लाभ लोगों को मिलेगा और जीरो बिल होगा ।

इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के नाते भी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं । अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो 90 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं । इससे महिलाओं का आत्मबल बढ़ता है, रोजगार भी मिलता है और वे किसी पर निर्भर भी नहीं रहती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में हर एक नागरिक को ?आयुष्मान भारत योजना? के नाते हर एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है । किसान निधि के नाते मुद्रा लोन के माध्यम से लोन की राशि भी बढ़ाई जा रही है ।, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा । मैं सरकार का ध्यान कुछ कार्यों की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

माननीय सभापति: कृपया, आप संक्षिप्त में कहें ।

श्री जुगल किशोर: महोदय, बिल्कुल संक्षिप्त में कहूंगा । जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं, जो करने हैं । मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी उन पर ध्यान दें और जम्मू कश्मीर प्रशासन की सहायता करें । वहां पर हमारे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, नीड बेसिस लोग हैं, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी आदि में काफी लोग काम कर रहे हैं, उनको नियमित करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम है । जम्मू कश्मीर को केन्द्र की सहायता चाहिए । मैं चाहूंगा उनको परमानेंट करने के लिए वित्त मंत्री कोई ऐसी योजना बनाएं, जिससे जम्मू कश्मीर सरकार को सहायता मिले । जो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी कैजुअल लेबर्स और नीड बेसिस लोग हैं, उनको नियमित किया जाए ।

महोदय, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि यह प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सोच है कि पीओजेके के रिफ्यूजी हों, चाहे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हों, कांग्रेस सरकार ने कभी भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उनको सारे अधिकार देते हुए उनका पुनर्वास किया है । मैं कहना चाहता हूं पीओजेके, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी और लोकल अलाटी को जमीन तो दी गई है, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया है । मैं चाहता हूं कि उनको मालिकाना हक मिले । यह इसलिए भी मिले कि प्रधान मंत्री किसान निधि का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, यह तब तक नहीं होगा, जब तक उनको मालिकाना हक नहीं मिलेगा । उनको जगह मिली है, वह उनको एलॉट है और वे खेती-बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए । दरिया चिनाब, तवी, बलोल और झेलम नदी पर बांध बनाने की बहुत जरूरत है । इसके लिए भी राशि मुहैया करवायी जाए । टूरिज्म के लिए परमंडल, उत्तरवाणी, खोड़ी, सुरिनसर, मंसर और पटनीटॉप का विकास करना भी बहुत जरूरी है । आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं । मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार प्रकट करता हूं कि वे जम्मू-कश्मीर की बेहतरी और विकास के लिए बहुत अच्छा बजट लेकर आए हैं । धन्यवाद ।

माननीय सभापति: जुगल किशोर जी, बजट पर सामान्य चर्चा के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का बजट भी यहां से पास होना है, उसके बजट पर भी चर्चा हो रही है । आपने जम्मू-कश्मीर के बिंदुओं को यहां रखा, इसलिए मैंने आपको अधिक समय दिया । लेकिन, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विषय को पांच मिनट में रखें ।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने जो वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया है, वह बेहद विभाजनकारी और निराशाजनक है । इस बजट में न किसान को कुछ, न संविधान का कुछ और न नौजवान को कुछ । यह बजट केवल धनवानों के लिए बनाया गया है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं । प्रधान मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास । मैं आपके माध्यम से, भारत सरकार के कुछ मंत्री यहां बैठे हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास की आपने चर्चा की है तो हरियाणा प्रदेश ने क्या कुसूर

किया है? हरियाणा प्रदेश की पेंडिंग परियोजनाएं हैं, जब यूपीए गवर्नमेंट थी, उस वक्त चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे । ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं । इसमें कैंसर रिसर्च सेंटर, जिस पर यहां भी चर्चा हुई है । हरियाणा सरकार ने 300 एकड़ से भी ज्यादा जमीन भारत सरकार को दी थी । लेकिन, भेदभाव की दृष्टि रखते हुए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और केन्द्र में एनडीए की सरकार थी, हमारे उस प्रोजेक्ट को आधा कर दिया गया । वहां 11 टावर और बनने थे, वे सारे बंद कर दिए गए । रिवाड़ी के एम्स को लेकर के पिछले सात साल से ड्रामा किया जा रहा है । आज तक वहां ईंट रखने के अलावा कुछ नहीं किया गया है । हिसार के दूरदर्शन केंद्र को, जब मैं केंद्र में मंत्री था, तब बनाया गया था । उसको इन्होंने बंद करने का काम किया है । आरआरटीएस रेल, जो दिल्ली से हिसार जानी थी और दिल्ली से सोनीपत होकर पानीपत जानी थी, वह प्रोजेक्ट तैयार था, लेकिन उसके लिए एक पैसे का फंड नहीं दिया गया है । रेल कोच फैक्टरी सोनीपत में बननी थी, लेकिन आज तक उसका कोई अता-पता नहीं है । मैं भारत सरकार के मंत्रियों से और भारत सरकार के प्रधान मंत्री जी से प्रश्न करता हूं कि हरियाणा प्रदेश इस देश का हिस्सा है या अलग है? आपका यह नारा ? ? सबका साथ, सबका विकास? थोथा है ।

महोदय, अब मैं दो-तीन इश्यूज़ पर चर्चा करना चाहता हूं । हिसार एयरपोर्ट का अभी तक यह पता नहीं लग रहा है कि वहां कार्गो बनेगा, नेशनल बनेगा या इंटरनेशनल बनेगा? उसका आठ बार शिलान्यास हो चुका है, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है । आठ साल से केन्द्र की सरकार हिसार और हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है ।

महोदय, कल मंत्री जी कह रहे थे कि एमएसपी के ऊपर हमने कोई वायदा नहीं किया है । मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह चिट्ठी है जो कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार की है । ?प्रिय महोदय, वर्तमान गतिशील किसान आंदोलन से लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से निम्न प्रस्ताव पेश किए जाते हैं ।? महोदय, जिस दिन यह समझौता हुआ, भारत के प्रधान मंत्री जी ने एमएसपी पर स्वयं और बाद में कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषाणा की । एमएसपी कमेटी में आज तक किसान मोर्चा के लोगों को शामिल नहीं किया गया है ।

दूसरा, एमएसपी को लेकर बहुत बेईमानी है । इसके अलावा मुआवजे का मुद्दा है । यह प्रधान मंत्री जी की चिट्ठी है । कौन विश्वास करेगा? कौन माननीय प्रधान मंत्री जी की गारंटी को मानेगा? जहां तक मुआवजे का सवाल है तो हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है । सर, तीन-तीन महीने से किसान हिसार में धरने पर बैठे हैं, लेकिन आज तक हमारे किसान को मुआवजा नहीं मिला है । इससे ज्यादा किसान विरोधी सरकार और क्या हो सकती है? अब मैं एमएसपी की चर्चा करना चाहूंगा । किसानों के लिए प्रधान मंत्री किसान निधि योजना है । इसमें एक साल के 6 हजार रुपये दिए गए हैं । ?प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना? दिनांक 24 फरवरी, 2019 को लागू की गई थी । उस वक्त डीजल का भाव 65 रुपये प्रति लीटर था । 200 लीटर डीजल भरवाकर आपने उसी समय 6 हजार रुपये पूरे कर दिए । आज का भाव 100 रुपये है और उस समय का भाव 65 रुपये था । वर्ष 2019 में भी किसान निधि 6 हजार रुपये थी और आज वर्ष 2024 में भी 6 हजार रुपये ही है । यह किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है । किसान के लिए आप एमएसपी लागू कर दीजिए कि हम आपको 6 हजार रुपये महीना दे देंगे और डीजल का भाव भी वर्ष 2019 का या वर्ष 2014 का लागू कर दीजिए ।

आपने किसानों के साथ बहुत बड़ी ... की है । जवान के साथ आपने बहुत बड़ी ...* की है । कल खाद की चर्चा चल रही थी । डीएपी वर्ष 2014 में 1400 रुपये प्रति कट्टा था और आज वह 2400 रुपये प्रति कट्टा है । यूरिया के अंदर आपने बड़ी चतुराई दिखाई । इसलिए हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि यह धनवानों की सरकार है

और वह कैसे है, उसके बारे में मैं बताता हूँ । इन्होंने यूरिया के दाम कम बढ़ाए, लेकिन उसमें से वजन कम कर दिया । पहले पांच किलो वजन कम किया, फिर पांच किलो बाद में कम कर दिया । इतनी चतुराई से देश के किसान को आप नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं इसलिए इस बजट को मैं किसान विरोधी, नौजवान विरोधी की संज्ञा देता हूँ ।

आप रोजगार की बात करते हैं । हरियाणा में कौशल रोजगार निगम बना । मैं थोड़ी सी गरीबों की बात कर लेता हूँ । कौशल रोजगार निगम में नौकरी लगती है । इसमें एससी/एसटी/ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है । दलितों और पिछड़ों के साथ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में धोखा किया गया है ।

जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे । हमने गरीब आदमी को, एससी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को 100-100 गज के प्लाट्स फ्री में दिए । हमने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टायपेंड दिया । हमने हर घर में नल दिया । हमारी सारी परियोजनाएं बंद करके आप इस देश के दलितों के साथ यह ड्रामा कर रहे हैं ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री जय प्रकाश : सर, एक मिनट दे दीजिए । मनरेगा विषय बहुत जरूरी है । इसके लिए देश का किसान आपसे भी लड़ जाएगा । उस समय भी मैं मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट था । इस देश में मनरेगा योजना यूपीए सरकार द्वारा लाई गई थी । उस समय डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे । उस समय 60 रुपये मजदूरी थी । आज कुल 200 रुपये मजदूरी है ।

अब मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि यदि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम 400 रुपये मजदूरी करेंगे और हरियाणा राज्य ने कहा था कि हम 600 रुपये मजदूरी करेंगे । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मनरेगा की मजदूरी 600 रुपये की जाए ।? (व्यवधान) सर, अग्निवीर का का मामला रह गया है ।

माननीय सभापति: आपकी पार्टी से पांच मिनट का समय एलॉट हुआ था । मैंने इनके लिए सात मिनट का समय दे दिया है ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है, आप कंक्लूड कर लीजिए ।

श्री जय प्रकाश: सर, मैं कंक्लूड करता हूँ । मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ । यह सरकार एच.सी.आई.ए. स्टाफ है । हरियाणा प्रदेश में कहते हैं कि जिस दिन से हरियाणा प्रदेश में पांच सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, उसी दिन से डेली हमारे यहां पर ई.डी. की रेड हो रही है ।

माननीय सभापति : अब आप कंक्लूड कीजिए । माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए ।

श्री जय प्रकाश: सर, हमारे विधायक जेलों में बंद हैं । हमारे नेता जेलों में बंद हैं । झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं ।? (व्यवधान)

पंचायती राज मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह): सभापति महोदय, सदन में आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट है, उस पर चर्चा हो रही है । यह बजट आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी जी की सरकार का क्या संकल्प है, उसको दर्शाने वाला बजट है ।

पिछले तीन दिन से सदन में जो चर्चा चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बजट पर भाषण देने के बजाय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की आलोचना पर यह पूरा बजट भाषण चल रहा है । ? (व्यवधान) आप भी बजट पर बोलिए ।?(व्यवधान) पूरे विपक्ष के भाषण का टोन यह दर्शाता है, जैसे नरेन्द्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो । ये उनसे नफरत कर रहे हैं । अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा? इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया है और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी है ।?(व्यवधान) मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है ।?(व्यवधान) यह उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है । उनके पेट में दर्द हो रहा है । इस देश की सच्चाई को अगर उसको वे नहीं पचा पा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है? ?(व्यवधान) हमारा इनको एक परामर्श है । ?(व्यवधान) आप बैठिए ।

श्री जय प्रकाश: सभापति महोदय, ?(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : हम आपका चरित्र भी बता देंगे । आप क्या करते रहे हैं??(व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप चेयर को संबोधित करें ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय जय प्रकाश जी, जब आप बोल रहे थे, तो आपको समय अधिक दिया गया और किसी ने व्यवधान उत्पन्न नहीं किया ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप परंपरा सीखिए ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप वरिष्ठ सदस्य हैं । आप बैठ जाइए । आप परंपरा सीखिए । आपकी स्पीच के समय किसी ने व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है । आपकी पार्टी को अवसर मिलेगा । माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं, उसका जवाब आपकी पार्टी देगी, आपकी पार्टी के नेता दे देंगे ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, ये कह रहे हैं कि कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे । वहां जा कर पता चला कि ? का काम ये लोग करते थे और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भइया वही काम करते रहो । ये लोग गठबंधन के अंदर लॉबी चलाते थे और लॉबी चला कर कैसे किस का मथ-फुटौवल करवाएं, इसकी योजना बनाते थे । हम लोगों ने प्रणाम किया और इधर चले आए । इसलिए छोड़ दीजिए, हम आपको बता देते हैं ।?(व्यवधान)

सभापति महोदय, इनको सच्चाई नहीं सुननी है । यह इनको पसंद नहीं है । हम यही कह रहे हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं, वह रिकॉर्ड में जा रहा है । किसी अन्य माननीय सदस्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है । केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है ।

?(व्यवधान)?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, हम इनको बता रहे हैं ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : सौगत राय जी, आप बैठ जाएं । जब मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा, तब आप बोलिएगा ।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Sir, I am on a Point of Order. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There is no Point of Order.

? (Interruptions)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, हम इनको बता रहे हैं कि जितनी जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा, उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो आपका पूरा मन विचलित रहेगा और पांच साल तक इसी तरह से विचलित रहिएगा ।

सभापति महोदय, 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है । पता नहीं गौरव गोगोई जी और अन्य लोगों ने लूडो खेला है या नहीं खेला है । लूडो खेल में जब 99 पर पहुंचते हैं, तब सांप काटता है, तब जीरो पर पहुंच जाते हैं । यही इनका हाल है । इसलिए ये जितनी जल्दी मन शांत कर लें और देश की सच्चाई को स्वीकार करेंगे, उतना ही इनको चैन मिलेगा । इनको चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा । इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम नरेन्द्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है, वह आगे बढ़ता रहेगा, उसमें ये व्यवधान डालने का प्रयास नहीं करें ।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Sir, I am on a Point of Order. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: There is no Point of Order during an hon. Minister?s statement or speech. आप लिख कर भेज दें ।

? (Interruptions)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : बजट पर ही स्पीच चल रही है । आप बैठ जाइए । क्या आपको बजट समझ में आता है? अभी हम एक-एक के बजट के भाषण के बारे में बता देंगे, तब बजट समझ में आ जाएगा ।

तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया, अब इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है । इनका एक एजेंडा रहता था कि इस देश में बेरोजगारी है, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है । इस पहले बजट में एक करोड़ लोगों के रोजगार के सृजन की चर्चा है । वह इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है । वह इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, इनका मन अशांत है । इनको वह कहां से दिखाई पड़ेगा?? (व्यवधान)

वास्तव में हुआ क्या है कि तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट आया है, मोदी जी की सरकार ने पहला बजट पेश किया और मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से जो पहली गुगली फेंकी, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं । उसी

बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं । विधवा विलाप किए जा रहे हैं । अरे, विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं । इस सच्चाई को स्वीकार करिये ।

अभी तो शुरुआत हुई है । यह तो पहला साल है, अभी आप पांच साल देखिये । पांच साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइयेगा, वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और जीरो पर पहुंचियेगा । यही होने वाला है । यहां कई लोगों ने, कई पार्टियों ने चर्चा की और कहा कि दो राज्यों को खुश करने की बात हुई है । अरे भाई, दो राज्यों को सरकार बचाने के लिए कई बातें हुईं, सरकार बचाने की कौन सी बात है? यह प्री-पोल अलायंस है और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, यह प्री-पोल अलायंस है । यह अलायंस फेविकोल से जुड़ा हुआ है । आपके साथ भी रहकर आपका चरित्र भी देख चुके हैं । आप ... हैं । सत्ता मिली नहीं कि कैसे सत्ता को खींचते रहे, आप लोग ये काम करते रहें । हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए । इसलिए आज चाहे जेडी(यू) हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री-पोल अलायंस में हम लोग सरकार में हैं और प्री-पोल अलायंस में पांच साल का पूर्ण बहुमत मिला है । आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं । आप चिंता मत करिये । ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, हम अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे ।? (व्यवधान) आप लोग यही काम तो आज तक करते रहे हैं । आप लोग यही काम करते रहे हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप चेयर को एड्रेस कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : ... है? यहां यह सब नहीं होता है । आप आराम करिये ।? (व्यवधान)

महोदय, हम अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे । अभिषेक बनर्जी जी ने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी की 4 जून, 2024 को जो पहली सरकार बनी which was rejected by the people of India. वाह रे भाई, आपके ज्ञान की हमें प्रशंसा करनी होगी कि पूर्ण बहुमत की सरकार है और आप कह रहे हैं कि rejected by the people of India. वाह! इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है । अभिषेक बनर्जी जी, आपको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए । इन्होंने भाषण में क्या कहा? वक्त बदल गया है । अभिषेक बनर्जी जी, हाँ, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं, इसलिए वक्त बदल गया है । आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें? आप आंख की जांच कराइये, चश्मा लगाइये । आपको दिखेगा कि इस देश की जनता ने क्या किया?

हम आशा करते थे, हम उम्मीद करते थे कि अभिषेक बनर्जी जी जब भाषण दे रहे थे तो वह कहते कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के चीरहरण का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर इस देश से क्षमा मांगते, लेकिन नहीं मांगी ।? (व्यवधान) वह नहीं मांगेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसे चीरहरण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और आम लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, वह उनको नहीं दिखता ।? (व्यवधान) अभी इसी सदन में? (व्यवधान)

अभी इसी सदन में? (व्यवधान) जय प्रकाश जी, आपको बता रहे हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करें ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : इसी सदन में *?* जी ने अपने मन की भड़ास और मन की तकलीफ को कई बार सदन के पटल पर उतारा था ।? (व्यवधान) पाँच साल तक ?दिशा? की मीटिंग नहीं हुई थी । पश्चिम बंगाल की सरकार ने ?दिशा? की मीटिंग नहीं होने दी और ये लोकतंत्र की बात करते हैं ।? (व्यवधान) इनको क्या अधिकार है लोकतंत्र की बात करने का ।? (व्यवधान) यह रेकॉर्ड में है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है, वह रेकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You must have patience to listen to me.

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : उन्होंने जिस माननीय सदस्य का नाम लिया है, वह रेकॉर्ड में नहीं जाएगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप चेयर को एड्रेस कीजिए । आप नाम मत लीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी को, वे भी थे यहाँ, वे इस सदन में प्रजेंट थे, जब *?* जी? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप उनका नाम मत लीजिए । वे अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप पूर्व सदस्य कहें ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : ठीक है । हमने उनका नाम विदड्रॉ कर लिया । महोदय, हमने उनका नाम वापस ले लिया ।? (व्यवधान) लेकिन सच्चाई है कि 17 वीं लोक सभा में, ? (व्यवधान) बैठ जाइए न जय प्रकाश जी, आप बैठ जाइए । ... ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपना भाषण करें ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि 17 वीं लोक सभा के दौरान? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : हुड्डा जी, जब आपका अवसर आएगा, तो आप बोलिएगा ।

? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hooda ji, I have already gone through Rule 355. There should be no Point of Order.

? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : इनको कहना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो चीरहरण हुआ, वह जायज़ था, आप यही कह दीजिए । आप देश के सामने यही कह दीजिए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं । इनकी बात खत्म होने दीजिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि कृपया आप अपना भाषण संक्षिप्त करें । आप माननीय सदस्य का नाम मत लीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : महोदय, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ । मैंने नाम वापस ले लिया ।? (व्यवधान) हमने नाम विदड्रॉ कर लिया ।? (व्यवधान)

हम कह रहे हैं कि 17 वीं लोक सभा में, उस समय माननीय विरोधी दल के नेता और सबसे बड़े विपक्षी दल के जो नेता थे, उन्होंने सदन के अन्दर कई बार अपनी पीड़ा का इज़हार किया कि उनके क्षेत्र में ?दिशा? की बैठक नहीं होने दी जा रही है । गौरव गोगोई जी बैठे हुए हैं । गौरव गोगोई जी उसके गवाह हैं । जय प्रकाश जी तो उस समय थे नहीं, ये कहाँ से जानेंगे । इसलिए गौरव गोगोई जी के सामने पीड़ा व्यक्त हुई । कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी ।? (व्यवधान) उसके बाद भी लगे हुए हैं, तो आप लगे रहिए । लगे रहिए मुन्नाभाई । ? (व्यवधान) कुछ न कुछ तो मिलेगा, लेकिन 99 वाला भी खतरा है, अगर साँप काटा, तो ज़ीरो पर आइएगा ।? (व्यवधान) लेकिन आप लगे रहिए । ? (व्यवधान) क्या करिएगा?

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है ।? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : हमने सैलजा जी का भी पूरा भाषण सुना । सैलजा जी का पूरा भाषण हरियाणा केन्द्रित था । यह देश का बजट है, हरियाणा का बजट थोड़े है? ? (व्यवधान) जय प्रकाश जी भी अभी बोल रहे थे? (व्यवधान) पूरा हरियाणा केन्द्रित है ।? (व्यवधान) यह देश का बजट है भइया, आप देश के बजट पर

बोलिए ।? (व्यवधान) श्री नरेन्द्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं । यह उनका संकल्प है ।? (व्यवधान) यह उनका आत्म विश्वास है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको बोलने का समय दूँगा ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं समय दूँगा । मैंने कहा है । जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं । आप सदन में डिक्टेट नहीं कर सकते । आप बैठ जाएं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने हुड्डा जी को कह दिया है । मैंने रूलिंग दे दी है । आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी का बजट भाषण हुआ, मैंने यह कहा कि पूरे तीन दिनों तक ये लोग बजट पर कम बोलते रहे, देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं था, इसलिए उनकी आलोचना में ये पूरे तीन दिन इन्होंने बिताए । ? (व्यवधान) बजट में जो प्रावधान हैं, वे इनको दिखाई ही नहीं पड़े । ? (व्यवधान) वे देखना भी ये नहीं चाहते हैं, इसलिए, क्योंकि ये तो पीड़ा में हैं, अंदर से कष्ट में हैं, विचलित हैं । ? (व्यवधान) मन जब विचलित रहता है, तो अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ती है । ? (व्यवधान)

इसलिए, मैं इनको कह रहा हूं । ? (व्यवधान) वित्त मंत्री जी के बजट के भाषण में साफ लिखा है कि नौ प्राथमिकताओं के संबंध में प्रयासों की परिकल्पना की गई है और वे नौ प्रयास देश को ?आत्मनिर्भर भारत? बनाने की दिशा में ला जाएंगे । ? (व्यवधान) यह इस बजट में है, यह इनको दिखा ही नहीं । ? (व्यवधान)

पहला क्या है? ?कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता?, ?रोजगार और कौशल प्रशिक्षण?, ?समावेशी मानव संसाधन विकास?, ?सामाजिक न्याय?, ?विनिर्माण और सेवाएं?, ?ऊर्जा सुरक्षा और संरचना?, ?नवाचार अनुसंधान और विकास? और ?अगली पीढ़ी के सुधार? । ? (व्यवधान) प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तो अभी की पीढ़ी के अलावा अगली पीढ़ी तक के लिए भी सोच रहे हैं । ? (व्यवधान) इनको यह दिखाई नहीं पड़ रहा है । ? (व्यवधान) जब दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? ? (व्यवधान) आपका मन विचलित है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके मन को जल्दी शांति प्रदान करे, मन की आत्मा का जल्दी से विचलापन खत्म हो, ताकि आप उससे बाहर निकलिए और देश की कल्पना के बारे में सोचिए । ? (व्यवधान)

इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें 4.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । ? (व्यवधान) यह इनको दिख नहीं रहा है ।? (व्यवधान) यह पूरे देश के लिए है, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए है । ? (व्यवधान) इनको यह नहीं दिख रहा है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2.65 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । ? (व्यवधान) यह इनको दिखेगा नहीं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि कृषि का बड़ा नुकसान हो रहा है । ? (व्यवधान) अरे, कृषि के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है । ? (व्यवधान) वह भी आपको नहीं दिख रहा है । ? (व्यवधान) शिक्षा के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । ? (व्यवधान) वह इनको नहीं दिख रहा है । ? (व्यवधान) स्वास्थ्य, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में 1.16 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । ? (व्यवधान) वह इनको दिख नहीं रहा है, इनकी नजर से ओझल हो रहा है । ? (व्यवधान) इनको दिख रहा है, तो सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिख रहा है और मोदी जी का चेहरा देखकर ये भड़क जा रहे हैं । ? (व्यवधान) कुछ और देख नहीं रहे हैं, लेकिन भड़केंगे, तो क्या करेंगे? देश की जनता को वही पसंद है, इसलिए वह चेहरा आगे बढ़ रहा है । ? (व्यवधान)

ऊर्जा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, कॉमर्स और इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो प्रावधान इस बजट में हैं, वे इनको दिख नहीं रहे हैं । ? (व्यवधान) इनको सिर्फ दो बातें दिख रही हैं । ? (व्यवधान) एक बात, मोदी जी का चेहरा, जो इनको पसंद नहीं है । ? (व्यवधान) जब देश की जनता उनको पसंद करती है, तो आपकी पसंदगी-नापसंदगी का कोई अर्थ नहीं है । ? (व्यवधान) आप जितना जल्दी उसको स्वीकार करेंगे और मोदी जी का चेहरा पसंद करने लगेंगे, उतनी ही जल्दी आपके मन को शांति मिलेगी । ? (व्यवधान) यह मैं आपको कह रहा हूं । ? (व्यवधान) दूसरा इनको बिहार और आंध्र प्रदेश दिख रहा है । ? (व्यवधान) अरे भइया, मैंने यह पूरा बता दिया । ? (व्यवधान) क्या इसमें सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश आता है? ? (व्यवधान) पूरे देश के विकास के लिए मोदी जी संकल्पित हैं, मोदी जी की सरकार संकल्पी है, ?आत्मनिर्भर भारत? बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । ? (व्यवधान) हम आगे बढ़ते रहेंगे, पूरे आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं । ? (व्यवधान) इसलिए, इस बजट का मैं समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : हरेन्द्र मलिक जी, आप बोलिए । आपकी ही बात रिकॉर्ड में जा रही है ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (मुजफ़्फ़रनगर) : सभापति जी, किसान के मामले में जो बात कही जा रही है, वह सही नहीं है । किसान को न तो सब्सिडी मिल रही है और जो किसान शहीद हुए थे उनके परिवारों को आज तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई है और बजट में उसका कोई प्रावधान भी नहीं है । नौजवान बेरोजगार हैं । केंद्र सरकार के 30 लाख पद खाली हैं । पढ़ाई महंगी हो चुकी है । मेडिकल की पढ़ाई गरीब का बच्चा नहीं कर सकता है । इंजीनियरिंग की पढ़ाई गरीब का बच्चा नहीं कर सकता है । पढ़ाई की फीस जितनी इस राज में बढ़ी है, ऐसा लगता है कि गरीब और किसान के बच्चों से किताब को छीनने का काम किया जा रहा है ।

महोदय, ये विकास की बात कह रहे हैं । लखनऊ में अखिलेश यादव जी द्वारा निर्मित केंसर अस्पताल, जिसमें एक हजार करोड़ रुपये की लागत लगी, वह बनकर खड़ा है, लेकिन उसमें डाक्टर और स्टाफ नहीं है । बेरोजगारी बढ़ी है । एमएसपी लागू करने का वायदा करके सरकार मुकर गई । किसान और नौजवान बरबाद और तबाह है । हमारी उम्मीद थी कि अग्निवीर को चार साल की बजाय 20-25 साल सर्विस का मौका देंगे परन्तु इस बजट में इन्होंने ऐसा भी नहीं किया । चारों तरफ हाहाकार मचा है । आप छह हजार रुपये किसान को देते हैं । इतने में दो

कट्टे डीएपी के आते हैं । हमें उम्मीद थी कि आप ट्रैक्टर पर जीएसटी खत्म करेंगे, एग्रीकल्चर में काम आने वाले संसाधनों पर जीएसटी खत्म करेंगे, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसान के ट्रेक्टर से 10 या 15 साल की सीमा हटा दी जाए । दूसरे इसके ऊपर जीएसटी खत्म कर दी जाए । चाहे पम्प सेट हो, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर हो या ट्रेक्टर के पार्ट्स हों, इन पर जीएसटी खत्म कर दी जाए । मेरा यह भी अनुरोध है कि जो किताब और पढ़ाई छीनने का काम किया गया है और फीस बढ़ाई है जैसे एमबीबीएस की पढ़ाई में एक करोड़ रुपये से कम का खर्च नहीं आता है, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है ।

रोजगार आप नहीं दे रहे हैं लेकिन कम से कम आप पुरानी पेंशन तो बहाल कर दो । ये सभी आपके वोटर हैं । आप पुरानी पेंशन बहाल करें । कैंसर अस्पताल का मैंने जिक्र किया है । लखनऊ में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से बना कैंसर अस्पताल तैयार खड़ा है । आप उसमें डाक्टर इसलिए नहीं भेज रहे, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार द्वारा निर्मित है । यह कहां का इंसाफ है? चारों तरफ विकास के नाम पर लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं है । कहीं विकास नहीं हो रहा है, केवल आपके नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का कहीं विकास नहीं हो रहा है । लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । हरिद्वार में हर हिंदू जाता है चाहे जिंदा जाए या मुर्दा जाए । आप हरिद्वार को टोल मुक्त कर दो । आप मेरे साथ सदन में थे, जिस दिन डॉ. अमर रिजवी ने सीतापुर में टोल लगाया था । आप ही कहने वाले थे कि जजिया कर देना पड़ेगा । आज आप हरिद्वार में भी जजिया कर ले रहे हैं ।

चारों तरफ जब आदमी सड़क पर चलता है तो टोल टैक्स देता है । कार, ट्रैक्टर आदि जो भी वाहन खरीदता है, तो टैक्स देना पड़ता है । डीजल, पेट्रोल लेते समय भी टैक्स देना पड़ता है । जब रजिस्ट्रेशन कराता है, तब टैक्स देना पड़ता है । आदमी कितनी बार टैक्स दे, यह समझ से परे की बात है । 750 किसान शहीद हों और देश के आदरणीय प्रधान मंत्री जी एक शब्द भी उनके शोक का न लिखें, इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती है । आदरणीय कृषि मंत्री जी को कोई पूछता नहीं है । कृषि मंत्री जी क्या वायदा करके आए, उस पर कोई काम नहीं हुआ । एमएसपी आज तक लागू नहीं हुई ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि किसान ही जीडीपी का सबसे बड़ा अंश है । हिंदुस्तान का पेट पालने का काम किसान करता है । आपने उनके साथ सिंधु बार्डर पर जो व्यवहार किया, उसके बारे में कभी रात में बैठकर सोचना कि इससे ... व्यवहार कुछ हो ही नहीं सकता है । उस किसान के साथ जिसका बेटा जवान बनकर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए खड़ा है । आज उसके रास्ते में कीलें ठोक दी गईं, सीमेंट की दीवार बना दी गई । हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ड्रोन से तीन सौ आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उस अन्नदाता के ऊपर छोड़े गए, जिससे वोट लेकर आप यहां बैठे हैं । क्या आपको ...* नहीं आई, क्या आपको अफसोस नहीं हुआ? कम से कम एक शब्द अफसोस का ही कह दें । मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी बात सदन में रखने का मौका दिया ।

SHRI DURAI VAIKO (TIRUCHIRAPPALLI): Respected Chairperson, Sir, I thank you for the opportunity given to me to express my views on the Union Budget.

The Indian Constitution clearly affirms India as a secular, socialist, sovereign and democratic republic, ensuring that its citizens get liberty, equality and justice. Federalism is an integral part of our republic that ensures diversity, peace, stability and mutual accommodation in a multi-cultural, cultural and diversified country like

ours. However, the Union Government and the Budget have abandoned key aspects of both the Constitution and the federalism.

My State of Tamil Nadu has been neglected in the Union Budget though the State is the second largest economy contributing nearly 8.8 per cent to the nation's GDP and also contributing 10 per cent to the country's total exports. Though my State accounts for nearly six per cent of the country's population, Tamil Nadu's share from the total divisible pool of Central taxes has decreased to just four per cent. In spite of numerous letters by our hon. Chief Minister, Mr. M. K. Stalin, seeking Rs. 37,907 crore for flood relief, the Centre had sanctioned a mere Rs. 276 crore, that too, after the Supreme Court's intervention. However, the Central Government with a step-motherly attitude has allotted thousands of crores of rupees for flood mitigation measures to other States. Is this because Tamil Nadu is the land of Thanthai Periyar and Perarignar Anna? Is this because we believe in the teachings of Mahatma and Babasaheb Ambedkar, and we do not believe in the teachings of Veer Savarkar and Godse?

Sir, though a budget of Rs. 24,930 crore has been allotted to MRTS and Metro projects in this Union Budget, it is highly disheartening to note that the second phase of Chennai Metro and the much-awaited Metro projects in Madurai and Coimbatore have not been mentioned. Out of the cost of Rs. 63,000 crore for the second phase of Chennai Metro, our State Government has allotted so far Rs. 21,000 crore in spite of strained finances. The Central Government has not given a single paisa. Is this because Tamil Nadu denied the BJP even a single seat? Trichy city, a central hub of our State, has also been denied quick implementation of the metro rail project. Though the detailed feasibility reports and the detailed project reports for the Trichy Metro have been undertaken in the past, there are no measures in this Budget for implementing the project. Is this because Tamil Nadu does not believe in politics of hatred?

The long-pending demand for a new railway line from Thanjavur to Madurai *via* Gandharvakottai and Pudukkottai has also been ignored in this Budget. A part of this railway line was surveyed and sanctioned in the year 2012-13, and this was mentioned in the Pink Book of the Railways till 2018-19. The much-needed Tambaram-Chengalpattu elevated expressway to decongest the traffic in the Chennai city has also been ignored in this Budget. Is this because Tamil Nadu does not believe in divisive politics? The Union Budget has not only neglected my State

of Tamil Nadu but also ignored the interests of the farmers, youth, poor and women of our country.

Sir, the growing divide between the haves and the have-nots in our country is alarming and shameful. Ten per cent of our population holds 77 per cent of our nation's wealth. A handful of corporates have immensely profited at the expense of the MSME sector. A billionaire spends Rs. 5,000 crore for a wedding in his family whereas more than 10,000 farmers commit suicide every year due to mounting farm debts. This Budget fails to legalise the guarantee for MSP based on the M.S. Swaminathan Commission formula of C2-plus-50 per cent. This Budget also fails to provide pensions, waivers on farm loans and compensation for more than 700 farmers who lost their lives during the 2020-2021 farm protests.

There has been no waiver of GST on farm inputs like seeds, pesticides and fertilizers. The demand to reduce GST on pesticides from 18 per cent to five per cent has been ignored. The allocation for agriculture and allied sectors as a percentage of the total Budget has been continuously declining from 2019 onwards from 5.4 per cent to the present 3.15 per cent.

In a stark contrast to the all-is-well story of the Union Government, the unemployment ratio and inflation, the true indicators of the nation's economy, portray a very grim picture. Unemployment ratio is at an all-time high of 9.2 per cent. Food inflation has crossed the 10 per cent barrier. India ranks a pathetic 111 out of 125 countries in the Global Hunger Index.

This Government for the past 10 years boasts of its love for the Indian youth. However, more than 10,000 youth commit suicide every year due to the stress caused by mounting education loans, unemployment and a faulty education system plagued by question paper leaks and scams.

All the announcements in this Budget about lakhs of crores allotted for upskilling and employment opportunities for the youth are nothing but false promises, just like the lie of doubling the farmers? income made in 2016 by this very Government.

I would like to conclude my speech by saying that this Budget is not a Budget for the farmers, poor, youth and women. On the contrary, it is a Budget that has been drafted to keep this Government alive by appeasing its coalition partners, and it is rightly called the ?Nitish-Naidu Budget?.

I also say that this Budget aids crony capitalism. It is a Budget which goes against the basic tenets of the Constitution, that is, equality and justice. It is a Budget that goes against the spirit of Ambedkar's federalism.

I humbly request the Union Government to transcend political boundaries and ideologies to serve the common man and this great country.

Thank you, Sir.

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Hon Chairman Sir, Vanakkam. I congratulate Hon. Finance Minister Smt. Nirmala Sitaraman for presenting the Budget in Parliament for the 7th consecutive time. I am happy to say that our Finance Minister has her roots linked to Viluppuram which is very near to Puducherry. I say this because she knows the ground reality of our area very much. Hon Finance Minister, while presenting her first Budget in the year 2019, brought a big idea of making India a five trillion economy.

Whether she has succeeded in achieving this target of 5 trillion economy? I should say they haven?t. While presenting the current Budget in 2024, she claims that India has achieved to be the fifth largest economy of the world. But in India, the per capita income of an individual person is approximately around Rs 2.5 lakh per annum. But we see our 80 Crore population living as poor. If we see their per capita income, it is not more than Rs 4000 per month. Moreover their lives are in a pitiable condition. They are severely affected by price rise.

Today a bag containing 25 kg of rice is sold at Rs.1700 whereas it was sold at Rs.700 earlier. Similarly the price of wheat has increased from Rs. 30 to Rs. 65 per kg. Price of Tamarind has increased from Rs.45 to Rs.65 per kg. Ten eggs were sold for Rs.10 earlier and now it is being sold at Rs.60. Even the price of pulses has risen from Rs.70 per kg to Rs.140 per kg. The people of our country are worst affected by this price rise. Even in MGNREGA, Rs.250/- was provided as daily wage earlier and it has now increased to just Rs.300/- per day. Those who are less educated like school pass outs are able to get a salary of only Rs.6000/- per month.

Moreover, graduates are provided only a meagre salary of less than Rs.12000/- per month. Whether farmers are getting remunerative prices for their produce? The answer is No. The prices of fertilisers and insecticides have gone up making the farm input cost unbearable for farmers. Whether the farmers are getting necessary loans? The answer is No. I should also say that the women working in informal sectors are not even getting their salaries well in time. Whether the housewives are

enjoying their rights? I should say the answer is No. This is the ground reality of today.

These women are not having economic freedom in their lives. They do not have security. That is why our leader Shri Rahul Gandhi called for restoring the rights of women in the society. Poor people suffer a lot. People do not like this Government which has never thought about the people?s welfare. As a result, BJP today is a minority Government. INDIA Alliance made this possible and the people of this country have given a strong verdict to make BJP Government a minority Government. You gave up Uttar Pradesh, the land of Lord Sri Ram and thereafter you gave up Lord Shri Ram himself, whom you worshipped for long. We can raise slogans like ?Jai Shri Ram?. But you will now say ?Jai Jagannath? instead of ?Jai Shri Ram?. You have totally forgotten the States like Maharashtra and Haryana.

You forgot your birth place, the Devbhoomi. You ignored Varanasi, which brought you up. You did not take care of Ayodhya, where Lord Rama was given birth. You have forgotten the places where you were given birth, where you were brought up and where you lived. You should help them in a way they needed help. You should help these States in a way you helped States like Andhra Pradesh and Bihar. Similarly you have given assurances to Puducherry. You assured to give adequate funds to this State. You talked about development of education and tourism in Puducherry. But Puducherry did not get anything. Last year you gave Rs.3,389 Crore and this year you have given only Rs.3,269 crore which has seen a reduction of Rs.120 Crore as compared to last year.

The Government of Puducherry is managing the administration of Power sector very well in the State. There is no loss to this Department. Therefore, it should never be privatised. If there is any such move to privatise the Power Sector of Puducherry it should be withdrawn besides allocating adequate funds to Union Territory of Puducherry. Thank you.

सुश्री कंगना रनौत (मंडी) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आज मुझे आपने वर्ष 2024 के इस बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है । साथी ही मंडी क्षेत्र की जनता, जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहां उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भी आभारी हूं ।

महोदय, यह जगह मेरे लिए बहुत नई है । मैं एक नई सांसद हूं, मगर मुझे इस बात का आभास है कि जो 18 वीं लोक सभा है, यह कोई सामान्य लोक सभा नहीं है । इस लोक सभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों

का रिकॉर्ड तोड़ा है । उसके लिए हम सब उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं । साथ ही हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ ।

मैं यह भी मानती हूं कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है, वह भी बधाई के पात्र है ।

महोदय, हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था । आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील, एक चरमराती और लड़खडाती अर्थव्यवस्था, जो कहीं 11-12 वें नंबर पर थी और सारा देश उसको लेकर चिंतित रहता था ।

पिछले 10 सालों में वह अर्थव्यवस्था 11 वें से पाँचवें नंबर पर आई है और बहुत तीव्रता से तीसरे नंबर की तरफ जा रही है । वर्ष 2024 का जो बजट है, यह सब वर्गों को शक्ति प्रदान करने वाला बजट है । इस बजट से हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी ।

महोदय, वर्ष 2047 का हमारा जो संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प है कि हम प्रथम इकोनॉमी बनेगें । वह भी इस बजट से पूरी उम्मीद है । हम उस संकल्प की तरफ एक कदम करीब जाएंगे ।

महोदय, पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया । वहां एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिससे हमारे लोगों की न जाने कितने जन, धन, पशु, जमीन की हानि हो गई । लेकिन, दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश उस त्रासदी के प्रभाव और हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है ।

इसका जो मूल कारण है, वह है वहां की कांग्रेस की सरकार । उनकी जो लापरवाही है, उनकी जो भ्रष्टाचार वाली नीतियां हैं, उससे आज भी हमारे लोग उस बाढ़ के प्रभाव से पीड़ित हैं । मैं आदरणीय और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए एक स्पेशल रिलीफ फंड की घोषणा की है । हम सब हिमाचलवासियों की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं ।

महोदय, मुझे आपको यह बताकर खुशी भी होती है और खेद भी होता है कि जितना काम पिछले दस वर्षों में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है, उतना काम आजादी के बाद 60 सालों में भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ था । आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे । ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. It is her maiden speech. Let the hon. Member speak.

14.00 hrs

सुश्री कंगना रनौत: आप सब हिमाचल जाते रहे होंगे, आप सबने देखा होगा कि आजादी के 60 सालों तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे । माननीय पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी ने अपने कार्यकाल में ग्रामीण प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड्स बनाई थीं । पिछले 10 वर्षों में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को एम्स, ट्रिपल आईटी, आईआईएम जैसे वैश्विक स्तर के संस्थान दिए हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल प्रदेश में पहुंचाया है ।

हमारे हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से राज्य को साढ़े 3 हजार करोड़ रुपये की लागत का मनाली- कीरतपुर हाईवे दिया है, जिसमें 5 से ज्यादा टनल्स हैं और 37 से ज्यादा ब्रिजेज़ हैं । ऐसा वैश्विक स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां पर हमें मिला है । पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही अद्भुत इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्बल है, जैसे कि 9 किलोमीटर की अटल टनल विश्व की सबसे लंबी टनल है । वह एक सिंगल ट्यूब हाइवे पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है ।

इसके साथ ही 11 हजार करोड़ रुपये के हाइडल प्रोजेक्ट्स हमारे हिमाचल प्रदेश को दिए हैं । अगर यह सूची मैं यहां पर रखूं तो शायद आप लोगों का बहुत वक्त इसमें लग जाएगा । लाखों लाभार्थियों को लाभ मिला है, चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे मकान हो या आयुष्मान हो, हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जो पूरी तरह से शौच फ्री है और वहां घर-घर में गैस चूल्हे का कनेक्शन लगा है ।

14.02 hrs (Shri Dilip Saikia *in the Chair*)

एक भी माता, एक भी बहन गैस चूल्हे के कनेक्शन के बिना नहीं है । मेरा यह सौभाग्य है कि जब मैं यहां पर आई थी, तब महिला आरक्षण बिल, जो राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देता है, वह बिल पारित हुआ था ।

मेरे लिए यह बड़ी ही सौभाग्यशाली 18 वीं लोक सभा है । मैं यह कहना चाहूंगी कि यह जो बिल है, यह अवश्य ही, इंप्लायमेंट हो या स्टार्ट अप इनोवेशन्स हों, चाहे हमारे गरीब और मिडिल क्लास को टैक्स रिलैक्सेशन हो या हमारे अन्नदाता किसान हों, उन पर फोकस हो, मैं इसे होलसम बजट कहती हूं ।

सरकार से मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि हमारे मंडी क्षेत्र में अगर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो टूरिज्म की दृष्टि से अवश्य ही हमारी जनता का बहुत कल्याण होगा । आप जरूर इस विषय में सोचें । यह जो बजट है, हम हिमाचल वासी इसका पूरी तरह से वेलकम करते हैं । धन्यवाद ।

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर (संगरूर) : सभापति जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद । पूरे बजट में मेरे प्रदेश पंजाब का जिक्र तक नहीं किया गया । मैं विरोध दर्ज करवाते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा । जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो दीवारों पर एक नारा लिखा रहता था, हम दो हमारे दो । पूरे देश के लोग जानते हैं कि पिछले दस सालों से दो साहब की सरकार चल रही थी । अब उन दो साहब के कंधों पर और दो लोग बैठ गए हैं । वह पुराना नारा पूरी तरह फिट हो गया, हम दो, हमारे दो ।

सभापति जी, इस सरकार का नया नारा सबका साथ, सबका विकास । मुझे लगता है कि दो का विकास बाकी सबका सत्यानाश, इस बजट में सारा कुछ दर्शाया जा रहा है । जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, यह स्वाभाविक है कि सभी लोग अपना रिजल्ट देख रहे थे, पूरे देश का भी रिजल्ट देख रहे थे । किसकी सरकार बन रही है, जब बीजेपी की सुई 230-240 के बीच अटकी हुई थी तो हम सोच रहे थे कि पांच-दस सीट और कम हो जाए, और कम हो जाए । लेकिन मैं अब कहता हूं कि भगवान का शुक्र है कि आपकी 240 सीट आ गई । अगर पांच-दस और सीटें कम हो जातीं तो पता नहीं नायडू बाबू के साथ कोई और बाबूजी आ जाते, इस वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा और किसानों का बजट और कम हो जाता ।

मैं समझता हूं कि पिछले 70 वर्ष से इतना मजबूरीवश बजट किसी सरकार ने पेश नहीं किया होगा जितना इस बार एनडीए सरकार ने पेश किया है । मैं समझता हूं कि जितने विपक्ष के साथी हैं, वे इस बजट से बहुत खुश

होंगे जैसे हरियाणा वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, उनके वहां इलेक्शन भी है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सरकार की मजबूरी समझिए, ?यूं ही कोई इतना बेवफा नहीं होता कुछ तो मजबूरियां रही होंगी ।? मजबूरी सिर्फ यही है कि सिर्फ सत्ता वाली कुर्सी बचानी है । उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए । आपने अपने बजट में चार बातों का जिक्र किया, युवा, किसान, महिलाओं और गरीबों का ख्याल इस बजट में रखा गया है । किसानों से वादा किया गया था कि उनकी आमदनी दोगुना करेंगे, एमएसपी का वादा किया गया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें 27 परसेंट फर्टिलाइजर पर सब्सिडी कम करके किसानों पर नया बोझ डालने का काम किया गया है । इससे उनकी आमदनी और कम कर दी गई । आपने कहा कि गरीबों की सरकार है, गरीबों को सबसे बड़ा बेनिफिट मनरेगा से मिल रहा था, उसका भी बजट कम कर दिया, उसमें जो महिलाओं की बात इसमें की गई है । सबसे ज्यादा महिलाओं ग्रामीण क्षेत्र में यदि कहीं से इनकम थी तो मनरेगा से थी, यह बड़ी शर्म की बात है । आपने न गरीबों को छोड़ा, न महिलाओं को छोड़ा, उसके बाद युवा की बात की गई । आपके इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया कि भारत युवा देश है, यंगिस्तान है । यहां एआई पर रिसर्च नहीं हो रहा है । रिसर्च पेपर की अगर हम अमेरिका या चीन से कम्पेरिजन करें तो बहुत पीछे हैं । उसके लिए फंड देने की जरूरत थी । बड़े दुख की बात है कि आपने आईआईटी का बजट कम कर दिया, आईआईएम का बजट कम कर दिया, क्या इस तरह से हम देश को आगे लेकर जाएंगे? अभी मैडम जी बात कर रही थीं कि दस साल पहले ऐसे था, दस साल पहले वैसे था । सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा, पूरी दुनिया में भारत की पोजिशन देखनी है, हैपिनेस इंडेक्स में 2016 में हम 118 वें नम्बर पर थे, अब 126 वें नम्बर पर चले गए । ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 125 देशों की सूची में 111 वें नम्बर पर हैं । हमारे पड़ोसी देश जिनको हम मुल्क भी नहीं समझते, वह भी हमारे देश से आगे निकल रहे हैं । सबसे हैरानी की बात है एक रिपोर्ट में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों का सर्वे किया गया, बड़े दुख की बात है कि हम 180 वें नम्बर पर हैं । हमसे एक देश भी पीछे नहीं है । जबकि हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरू बनेंगे । सिर्फ बात करने से विश्व गुरू नहीं बनेंगे, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ सवा चार करोड़ लोग हैं, जिनकी महीने की कमाई 25 हजार रुपये से ज्यादा है । आप सोचिए कि जिनकी महीने की सैलरी 25 हजार रुपये से कम है, क्या वह सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहा होगा । यहां माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व से कहा कि 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, यह कोई गर्व की बात नहीं है । मुझे लगता है कि यह सरकार के लिए शर्म की बात है । पिछले दस सालों में 85 करोड़ लोगों को गरीबी से नहीं निकाल पाएं और और इस चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं । देश ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा ।

महोदय, मैं अंत में पंजाब की बात कहना चाहता हूं, वैसे तो किसी भी प्रदेश का ध्यान नहीं रखा गया । आपने फ्लड्स के लिए बजट अलॉट किया । आपने कहा कि असम, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई तो क्या पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड में जो बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई क्या पहाड़ों में रुक जाएगी? उस बारिश का पानी पंजाब में आया और पंजाब में 1680 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ । मैं उस समय इरिगेशन मिनिस्टर था । मैं तरनतारन, कपूरथला, मोहाली और रोपड़ गया था । वहां तीन फुट मिट्टी चढ़ गई है । मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां ऐसा माहौल बन गया है कि अगले 20 साल खेती नहीं हो सकती है ।

महोदय, मैं पंजाब के प्वाइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूं कि पंजाब से इतनी नफरत क्यों है? पंजाब का बलिदान बहुत बड़ा रहा है । देश को आजाद करवाने में 80 प्रतिशत कुर्बानियां वहीं से हैं । आज भी आप पंजाब के किसी गांव में जाएंगे तो कोई भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां शहीद की मूर्ति न हो । पंजाब के लोगों ने सरहद की रक्षा करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दीं । आज भी ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि पंजाब के गांवों में तिरंगे में लिपटी नौजवान की लाश न आती हो । आप उसका जिक्र तक नहीं करते । आप किस बात के आधार पर कह रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर हो गया? आत्मनिर्भर करने में सबसे बड़ा योगदान किसानों का ही है । यह सब ऐसे ही नहीं

हो गया है? हमें मूल्य उतारना पड़ा है । हमने अपना पानी बर्बाद कर लिया, अपनी धरती बर्बाद कर ली । पंजाब से कैंसर ट्रेन राजस्थान जाती है, क्योंकि देश का पेट भरने का काम पंजाब कर रहा है और इसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं? आपने हमारी झांकियां तक 26 जनवरी की परेड में से निकाल दीं ।

मेरी मांग है कि पंजाब को स्पेशल पैकेज दिया जाए । हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है । मैं कहूंगा कि यह बजट केवल कुर्सी बचाने वाला बजट है, इसमें देश, देश के किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं है ।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : माननीय सभापति जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट पर चल रही चर्चा में बोलने का मौका दिया ।

महोदय, तीसरी बार इनकी सरकार बनी है । देश के जवानों, मजदूरों, किसानों और सारे समाज को बहुत उम्मीद थी लेकिन बजट से आम जन को निराशा ही हाथ लगी है । मैं राजस्थान के नागौर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार चुनकर आया हूं । आपको वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में राजस्थान से 25 सीटें मिली थीं, राजस्थान को आपसे बहुत उम्मीदें थीं लेकिन राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के वर्गों को इस बजट से निराशा ही हुई है ।

मैं दो दिन से चर्चा सुन रहा हूं । पक्ष तो बढ़ा-चढ़ाकर बात कर रहा है लेकिन विपक्ष इसे कोस रहा था । बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया गया है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है क्योंकि वह भी हमारे भाई हैं । वर्ष 2014 और 2019 में हम सब आपकी सरकार लाए थे और अब भी आपके साथ हैं, आपको इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए । इसमें देश के अन्य राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए था । जब यहां बजट प्रस्तुत हुआ तो राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया ? पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया, राजगीर, दरभंगा में सड़कों के कामों में तेजी लाई जाएगी, बक्सर में गंगा नदी वाला पुल बनेगा, 26,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं, राजस्थान में जब इसकी आलोचना हुई तो उनको अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा क्योंकि उनको लगा कि चूक हो गई । राजस्थान में तो आपकी पार्टी की सरकार है । जहां आपकी पार्टी की सरकार है, व्यथित होकर मुख्यमंत्री जी को ट्वीट वापस लेना पड़े, मेरे हिसाब से यह मामला ठीक नहीं है । राजस्थान के आठ करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, हमेशा आपके साथ खड़े रहे लेकिन उनके साथ धोखा हुआ ।

एमएसपी को लेकर सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ और यह लंबे समय तक चला । इसमें 700 से ज्यादा किसानों ने शहादतें दीं । तब मैं एनडीए का हिस्सा था । किसान आंदोलन के समय अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए को छोड़ा और किसानों के हक के लिए मैं भी आपको छोड़कर अलग हुआ । आपके यहां से कई सांसद कहते थे कि अगली बार कैसे जीतकर आएंगे?

महोदय, अबकी बार हम जीतकर भी आए हैं और 11 लोगों को राजस्थान से साथ लेकर भी आए हैं । यह आप जानते हैं । आपने एमएसपी के लिए जो वादा किया था, उसको आपने कुछ बढ़ाकर बात कही है । हम चाहते हैं कि एमएसपी की पूरी खरीद हो और किसान को उसका हक और अधिकार मिले । आपने जो वादा किया है, आप उस वादे को निभाइए ।

महोदय, अगर मैं किसान कर्ज माफी की बात करूं तो 30 जून, 2023 को इसी लोक सभा में जब आपकी सरकार ने मेरे सवाल का जवाब दिया था, उसमें किसानों के कर्जे की स्थिति बताई थी । वह बहुत चिंताजनक थी । केवल मेरे राजस्थान के किसानों पर 1 लाख 47 हजार 538 करोड़ रुपये का कृषि कर्ज बकाया है । इसलिए,

मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए राजस्थान सहित देश के सभी किसानों की कर्ज माफी करने का एक निश्चित रोडमैप बनाया जाए तथा ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए ।

महोदय, इन्होंने 15 लाख करोड़ रुपये धन्ना सेठों का माफ किया है । पिछली सरकार हो या कोई भी सरकार हो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह एक सरकार की बात है, लेकिन किसान कर्ज माफी की चिंता किसी ने नहीं की । अगर 15 लाख करोड़ रुपये धन्ना सेठों का माफ हुआ है तो 15 लाख करोड़ रुपये किसान का जो कर्ज है, वह संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए ।

महोदय, इस बजट में कृषि बजट और सरकार के स्पष्ट विजन का अभाव दिखा । यह पहले से थोड़ा-सा ज्यादा जरूर है । माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा । इसलिए जरूरत पर आधारित 10 हजार इनपुट रिसोर्ट सेंटर के लिए 365 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । पिछले साल इसके लिए 459 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन खर्च केवल 100 करोड़ रुपये ही हुए थे । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके पास प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर कामयाब उत्पादन प्रकिया के रूप में परखने का कोई पुख्ता पैमाना है? क्या इस विषय को लेकर आपने कभी देश के वैज्ञानिक समुदाय की राय ली है?

महोदय, आज भी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था । अग्निवीर की तारीफ हो रही थी । अग्निवीर के खिलाफ अगर देश के अंदर कहीं आंदोलन हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया है । जोधपुर में 2 लाख युवाओं ने बड़ी रैली की । राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान के बेटे हमेशा शहादत देते आए हैं । 20 हजार फीट ऊँची पहाड़ियों पर 50 किलो गोला-बारूद, एके-47 और एके-56 के साथ उन्होंने कारगिल के अंदर भी लोहा मनवाया है । लेकिन, अग्निवीर से हर कोई परेशान है । पंजाब के अंदर जब दो अग्निवीर शहीद हुए और जब उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से आया तो लोग अचंभित हो गए कि कौन आया और कौन नहीं आया । उनके लिए न पेंशन की व्यवस्था है और न उन्हें शहीद का दर्जा देने की बात की गई है । अभी प्रधान मंत्री जी हरियाणा का चुनाव हार गए और राज्यों के चुनाव में भी आपके जो कई कैंडिडेट्स हारे थे, उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना की वजह से हारे हैं । अग्निवीर योजना को बंद किया जाए ।

महोदय, मैं दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दों को रखकर जल्द ही अपनी बात समाप्त करूंगा । हम आपकी योजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि देश का जवान इसका विरोध कर रहा है । सेना का सम्मान कैसे हो? किस तरह से लोग शहीद होने के लिए जाते थे, हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन अब लोग सेना में जाने से कतराने लगे हैं । मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां हों ।

महोदय, कौशल विकास और बेरोजगार के बारे में कहा गया है कि 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के प्रावधान की बात कही है । आपने झुनझुना तो पकड़ा दिया, लकिन केंद्रीय नौकरियों में जो पद खाली हैं, उनको भरने के लिए आप आदेश दीजिए । आपने स्किल डेवलपमेंट की बात कही है । हरियाणा के बाद राजस्थान की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है । इसलिए, मेरा एक सुझाव है कि केवल स्किल देने से हम रोजगार नहीं दे सकते हैं । हमें यह भी देखना होगा कि क्या समय के साथ उसमें कोई बदलाव आया है? जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, क्या वे सब्सिडी या सरकारी सहायता से तो नहीं चल रहे हैं? जब वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार बनी तब क्रूड ऑयल का क्या भाव था और आज क्या भाव है । क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, बावजूद इसके पेट्रोल-डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं । पेट्रोल-डीजल की बढ़ती दरों का असर महंगाई पर पड़ रहा है । आज हालात क्या

हैं? महंगाई बहुत है, लेकिन आपने बजट में मध्यम और निर्धन वर्ग की महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया है । आपने कमर तोड़ दी है । मैं चाहता हूं कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हों ।

महोदय, मैं राजस्थान पर आ रहा हूं । मेरे राजस्थान राज्य को, जिस तरह से आपने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया है, राजस्थान राज्य के अंदर भी विशेष राज्य का दर्जा, जिसके लिए जो मापदंड होते हैं, वहां चम्बल के बीहड़, अरावली की लंबी पर्वतमाला और विशाल रेगिस्तान और ट्राइबल बेल्ट है, इन तमाम स्थानों पर विपरीत हालातों में राजस्थान के लोग रहते है, आजादी के दशकों बाद गाँव और ढाणियों में शुद्ध पीने का पानी नही है ।

आपने पढ़ा होगा कि 20-20 किलोमीटर पैदल मटका सर पर रखकर महिलाएं पानी लाती थीं । आज भी हम टांकों के अंदर बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं । आजादी के 75 साल साल बाद भी आज बड़े विकट हालात राजस्थान के अंदर है । ट्राइबल बेल्ट में कुपोषण से भारत के अंदर भूख से मौतें हुईं हैं । गाँव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं सहित बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है । मैं आपसे यह मांग करता हूं कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दें । अगर आप विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप राजस्थान को विशेष पैकेज दें । यह मेरी मांग है ।

महोदय, आपने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है । जो ईस्टर्न के जिले हैं, भारत सरकार इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दे, लेकिन आपने दर्जा नहीं दिया है । मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान के वे तमाम जिले, जिन्होंने अकाल के साए में अपना अतीत बिताया है और वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं । वहां के खेतों में सिंचाई और लोगों के पीने के पानी के लिए आप ईआरसीपी की तर्ज पर पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना (डब्ल्यूआरसीपी) की यहां से घोषणा करें । मैं आपसे ऐसी मांग करता हूं ।?(व्यवधान)

आप देश में ?सौभाग्य योजना? लेकर आए और प्रत्येक ढाणी का विद्युतीकरण किया है । सौभाग्य की संशोधित योजना लाए, लेकिन उसमें पूरा बजट खर्च नहीं हो पाया था । आरडीएसएस विद्युतीकरण करें । सौभाग्य की संशोधित योजना आरडीएसएस आई है । इसमें मेरा सवाल है, जिसमें आपने बताया है कि नागौर, डीडवाना-कुचामन जिले के लिए 15,615 घरों में विद्युतीकरण के लिए 25.57 करोड़ रुपये दिए गए हैं । अगर मैं केवल मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करूं, तो अभी के प्रावधान के अनुसार 45,000 रुपये तय किए हुए हैं । अगर 45,000 रुपये तक है, तो वह सरकार देगी । मेरी यह मांग है कि वहां बहुत ढाणियां हैं और वे दूर-दूर हैं, इसलिए 45,000 रुपये का राइडर हटाकर 80,000 रुपये तक किया जाए । इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा ।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिण्डा) : महोदय, मैं तो मांग करूंगी कि इस बजट का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि यह देश का बजट नहीं है, यह सरकार बचाओ बजट है । यदि देश का बजट होता, तो फिर देश में 28 राज्य हैं और कितने सारे केन्द्र शासित प्रदेश हैं, सब मिलाकर लगभग 37 राज्य हैं, लेकिन पूरे बजट में केवल 9 राज्यों का ही नाम था । उसमें सबसे ज्यादा बजट तो उन दो राज्यों को मिला है, जिनके कंधे के सहारे यह सरकार चल रही है । यह देश का बजट नहीं है, यह सरकार बचाओ बजट है ।

सबसे बड़े दुःख की बात तो यह है कि बजट में नैचुरल कैलेमिटीज और धर्म के नाम पर भी पक्षपात किया गया है । ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूं । बहुत अच्छी बात है कि आपने धार्मिक स्थानों - बोधगया, राजगीर, आपने जहां-जहां के लिए पैसा दिया है, बहुत अच्छी बात है । श्री दरबार साहिब अमृतसर पर रोज दो लाख लोग नतमस्तक होते हैं, उनको मुफ्त खाना मिलता है । वहां पर पूरी दुनिया और देश भर के लोग जाते हैं । जहां पर सारे दिन सबके भले की अरदास होती है, आपने उसका तो नाम तक नहीं लिया है ।

अगर मैं नैचुरल कैलेमिटीज की बात करूं, तो आपने राज्यों को फ्लड रिलीफ फंड दिया है । बहुत अच्छी बात है । जैसे मेरे सहयोगी ने मुझसे पूर्व बोला कि हिमाचल प्रदेश से जो पानी आता है, आपने हिमाचल प्रदेश को पैकेज दिया है, लेकिन जब हिमाचल प्रदेश का पानी पंजाब में पहुंचकर पंजाब को डुबो देता है और तबाही मचाता है, तो आप पंजाब को क्यों भूल जाते हैं? जब पानी डैम में भर जाता है, तो आप डैम खोल देते हैं और हमारा पंजाब डुबा देते हैं । जब घग्गर रिवर का लेवल ऊपर हो जाता है, तो आप चुपचाप साथी राज्यों को बचाने के लिए बांध तोड़ देते हैं और हमारे गांवों को डुबा देते हैं । जब बाढ़ आती है, आपने उनको पैकेज दिया है, मैं उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं, लेकिन हमारे राज्य के साथ क्या दुश्मनी है? क्या पंजाब की जनता, पंजाब के लोग, पंजाब के किसान और पंजाब का इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार के लिए मैटर नहीं करता है?

सर, हैरानी की बात है कि जब बाढ़ आती है, तो पंजाब सफर करे । जब पानी की कमी हो जाती है, तो फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, सारे इकट्ठे होकर षडयंत्र करते हैं कि एसवाईएल नहर बनाइए, ताकि पंजाब का पानी दूसरे राज्य में जाए । जब पानी कम होता है, तब तो आप हमारा पानी चुराना चाहते हैं । जब उसमें पानी ज्यादा हो जाता है, तब पंजाब को फ्लड में डुबा देते हैं ।

सर, मैं आपसे यह भी बताना चाहती हूं कि तकरीबन 70 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रिपेरियन सिद्धांत के खिलाफ हमारा पानी राजस्थान को दे दिया था । वे कहते थे कि एक साल में उस पानी की क्या कॉस्ट होगी, आपको डिसाइड करके मिलेगा । 70 साल के बाद भी आज तक डिसिजन नहीं हुआ है । हमारा जितना भी पानी रिपेरियन सिद्धांत के खिलाफ दूसरे राज्यों में जा रहा है, या तो उसको बंद किया जाए या हमें उसका पैसा दिया जाए । आज मैं आपके माध्यम से यह मांग करती हूं ।

महोदय, मैं आपसे एक और मांग करती हूं कि सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर कहता है कि पंजाब के सारे ब्लॉक्स क्रिटिकल हो गए हैं । हमारे वेल्स का पानी और नीचे जा रहा है । आज की रिपोर्ट तो यह भी है कि टॉक्सिसिटी इतनी हाई है कि पानी पीने के लायक नहीं है । हम लोगों की तो मदद करनी चाहिए । इस पूरे बजट में मदद की बात तो दूर रही, हमारा नाम तक नहीं लिया गया है । मैं यह डिमांड करती हूं कि पंजाब को भी वह दिया जाए । अब मैं किसानों के बारे में बात करना चाहती हूं । आपने चार पिलर बोले थे - युवा, महिला, गरीब और किसान ।

मैं किसानों के बारे में तो बोलना नहीं चाहती हूं कि कितने किसानों ने खुदखुशी कर ली है और शहीद हो गए हैं तथा आज तक धरने पर बैठे हुए हैं । अगर यह सरकार किसान हक की सरकार होती, जो कहती थी कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे तो आप मुझे इतना ही समझा दें कि अगर पॉलिसीज़ इतनी अच्छी हैं तो वर्ष 2022-23 में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो 4.7 थी, वह पिछले साल 1.4 क्यों रह गई?हकीकत यह है कि ये किसानों के दुश्मन हैं, किसानों के हिमायती नहीं है । आज आप महंगाई की मार देखिए कि 7-8 साल पहले 40 किलो का एक बीज का बैग होता था, वह 800 से 1200 रुपये का था, जो अब 2000 रुपये हो गया, डीएपी की कीमत तीन गुना बढ़ गई, पोटाश 900 से 1700 रुपये हो गया, लेबर की कॉस्ट तीन गुनी हो गई, हार्वेस्टिंग की कॉस्ट तीन गुनी हो गई, मशीन रेंटल होती थी और डीजल 47 से 90 रुपये कर दिया । इनको

किसान को रिलीफ देना चाहिए था । मनरेगा में जीरो इन्क्रीज है । लोग सोचते थे कि मनरेगा में अमाउंट या दिन बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें जीरो है । क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अमाउण्ट में माइनस 2.6 की कटौती की गई है, यूरिया ससिब्डी में माइनस 7.4 की कटौती की है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में माइनस 2.5 परसेट कटौती की, गरीब कल्याण योजना का बजट 3.3 परसेंट घटा दिया है, किसान सम्मान निधि का 10 परसेंट घटा दिया है और वर्ष 2018 से 2022 तक जितने फार्मर्स फसल बीमा योजना के अंडर कवर थे, सबका 8-9 परसेंट कट गया है ।

सर, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब बेनिफिशियरीज़ पीएम किसान निधि में थे और आवास योजना में वर्ष 2018 से आवास घटते ही जा रहे हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि जो किसान देश का पेट भरता है, किसान सबसे ज्यादा योगदान पाता है, जिनकी वजह से आप इन 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं, आप उस किसान के साथ दुश्मनी क्यों दिखा रहे हैं । मैं सरकार को अपील करती हूं कि स्वामीनाथन कमीशन की एमएसपी लीगल गारंटी C2+50% थी, उसको लागू करें । मैं दो-चार सजेशन देती हूं कि जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम भाव अंतर स्कीम लाइए । जिसकी एमएसपी पर नहीं बिक रही है तो जो बीच का रह जाता है, वह दें । आप एक फार्मर फ्रेंडली क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लेकर आएं, जिसमें किसानों का फायदा हो, इंश्योरेंस कंपनी का फायदा न हो । किसानों के जो इम्प्लिमेंट्स हैं, आप इन पर जीएसटी खत्म कीजिए, ताकि किसानों का कुछ फायदा हो और उनकी फल सब्जियां बचें । अब मानसून आ रहा है । अब टमाटर के रेट कहां चले जाएंगे? अगर आप इम्प्लिमेंट्स में जीरो करें तो बहुत फायदा हो जाएगा ।

सर, पंजाब की इंडस्ट्री के साथ की स्टेट्स को टैक्स इंसेंटिव देकर तबाह कर दिया, हमारी इंडस्ट्री भाग गई है । मैं इतनी विनती करती हूं कि सिंह साहब लुधियाना गए थे, जो वहां पर मंत्री बने बैठे हैं । वह लुधियाना गए थे, जहां पर उन्होंने एमएसएमई इंडस्ट्री को बोला था कि जो अमेंडमेंट 43-बी है, जिसमें मेंडेंट किया जाता है कि 44 डेज़ में पेमेंट कीजिए, अन्यथा आपके टैक्स इंसेंटिव फोरफीट हो जाते हैं । इस बजट में वह नहीं किया गया है । जो हमारी साइकिल इंडस्ट्री है, जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री है, उसके लिए मैं आपको विनती करती हूं कि इंटरनेशनल बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ वर्ष 2019 से हमारा वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, उससे बहुत नुकसान हुआ है । यह बॉर्डर खोला जाए । हमारे राज्य को बॉर्डर खोलकर कोई टैक्स इंसेंटिव साइकिल इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को दिए जाएं, ताकि हमारे इधर का व्यापार बढ़े और नौकरियां भी बढ़े । मैं आखिर में यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दस सालों में पंजाब के खजाने को लूटकर तबाह कर दिया है । हमारे छोटे से राज्य पर 3.4 लाख करोड़ रुपये का कर्जा चढ़ गया है और जीएसपीपी रेशियो 49 परसेंट हो गया है । आप इनको सजा देने के लिए आरडीएफ रोक देते हैं, हेल्थ मिशन का रोक देते हैं, लेकिन पंजाब के लोगों का क्या कसूर है?

सर, मैं आपसे विनती करती हूं कि हमारे पैसे को दीजिए । देश में जो अनएम्प्लॉइमेंट रेट है, उसका दोगुना हमारे यहां है । हमारा राज्य ड्रग एब्यूज से जूझ रहा है । पंजाब में औरतों का यह हाल है कि कुपोषण बढ़ गया है, एनीमिया बढ़ गया है । आंगनबाड़ी में जो राशन गरीब बच्चियों, लेक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट मदर्स और बच्चों के मिलता है, वह आम आदमी की सरकार ने वेरका मिल्कफेड प्राइवेट आधारों से लेकर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया और लोगों को सब स्टैंडर्ड चीजें देकर करोड़ों का घपला हो रहा है । सर, पैसे न रोकिए, बल्कि इनको पीनलाइज़ कीजिए, ताकि लोगों को अपना हक मिले । मैं यही कहूंगी कि सबसे हाइेस्ट एससी पॉपुलेशन 32 परसेंट पंजाब में है । पंजाब ग्रेनरी को सबसे ज्यादा योगदान देता है और हमने फ्रीडम स्ट्रगल में सबसे बड़ा योगदान दिया है । इस राज्य की मांगों को पूरी करके हमारे चण्डीगढ़ की राजधानी हमें दीजिए । हमारा पानी दूसरे राज्यों को जा रहा है, उसको रोककर उसकी रॉयल्टी हमें दीजिए, अन्यथा वे सारे फैसले रीवोक करके हमारा पानी पंजाब में रखिए । मैं आपसे यह विनती करती हूं । शुक्रिया ।

DR. DHARAMVIRA GANDHI (PATIALA): I thank you, Hon?ble Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on the Union Budget 2024-25. This is a budget of compulsion. This is a budget of a politically weak and unstable Government. This Budget ignores the federal structure of the Constitution. The interests of all other States except 2 States have been neglected.

Sir, all States had decided to join India as India has a federal structure. Punjab, Bengal, Tamil Nadu etc. have forsaken their identity and decided to join the Indian Union on the basis of federalism only. All States are to be treated as equal. The Constitution talks about Union List, State List and Concurrent List. In the last 10 years, many subjects belonging to State and Concurrent List have been removed from there and unilaterally put in the Union List. States are consistently being weakened financially. Centre has usurped all the powers of the States and States have been left with a begging bowl only. Except for Andhra Pradesh and Bihar, many other States are feeling ignored and marginalized. Their interests have been ignored.

Sir, the States contribute towards strengthening the G.D.P. of the country. Revenue is generated by the States. All natural resources and mines etc. are located in States. But States are being weakened consistently and their rights are being usurped by the Centre.

Sir, this Budget does not even mention Punjab. Punjab was at the vanguard in the freedom struggle. Maximum number of martyrs belonged to Punjab. A lot of sacrifices were made by Punjabis for protecting the country. During all wars, Punjabis were at the forefront. There were martyrs in a majority of villages of Punjab. When India was facing famines in the 1970s, Punjab became the harbinger of Green Revolution. India was importing foodgrains at that time from rich and developed countries. But, Punjab made India self-sufficient in foodgrains production. All credit goes to the farmers of Punjab. We had to suffer as our soil got degraded. Our air was polluted. Our river-water became polluted. Punjab needed Central help. But, no help was provided to Punjab. Agro-based industries were not provided to Punjab. Our industries in Batala, Gobindgarh etc. fled Punjab because H.P. and Haryana were given special industrial packages. The industries of Punjab migrated to neighbouring States in search of greener pastures.

Our youths are feeling frustrated. All avenues of youth for progress are blocked. So, drugs have become rampant in Punjab. Our youths are addicted to drugs. Others are migrating to foreign countries in search of better avenues.

Sir, India is a country dependent on agriculture. The farmers of Punjab made supreme sacrifices. They protested against black laws on the roads of Delhi. 750 farmers became martyrs to protect the interests of farmers. They wanted MSP for foodgrains to be given legal guarantee. The Government has not made any provisions regarding this in the Budget. Sir, Adani and Ambani are corporates who are friendly with the Central Government. They want to capture the millions of rupees worth of market of foodgrains production and storage. Farmers are being made scapegoats due to this reason. This budget does not give any MSP guarantee to farmers. Their loans have not been waived off.?(*Interruptions*)

Sir, let me conclude. I urge the Government to provide a legal guarantee for MSP of foodgrains. The loans of farmers must be waived off. The daily wages of MNREGA Scheme should be increased. The number of days of this Scheme should also be increased. Also, 20 lakh Government jobs must be filled. And old pension scheme must be implemented.

Thank you.

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI): Thank you, Sir, for permitting me to speak in this discussion on the Budget.

When we say that this Budget has failed to address the crucial issues confronting the nation and its economy, it is not a mere saying but an open fact. Even the inflation, which has severely affected the common people, has not been seriously addressed through this Budget. It is regretful that even after the eye-opening setback in the elections, the Government is not ready to open its sight and see the reality with neutrality. Here I would like to say:

?आँखें अगर हैं बंद तो दिन भी रात है,

इसमें भला कसूर क्या है आफताब का ।?

Sir, this is the position. The Government has to open its sight to see the reality straightly.

Sir, this Budget is a sign of the changed political landscape and the fractured verdict that the last Lok Sabha Elections have given to this Ruling Party. The verdict was against the single-party majority syndrome of the Ruling Party. That is why, we can understand that alliance is very crucial for the survival of the Government. But sacrificing the interests of the majority of the States for pleasing a few States will go against the principles of democracy and federalism. In our system, our fairness

is directly linked with federalism. Federalism means equality, neutrality, plurality, vividity which is there in the politics of the country, in the culture of the country, and in every sphere of our national life.

Sir, a tree can become a tree only with leaves, and it should give shadow to everybody who comes under it. While thinking of this Government?s policy, I am reminded of a couplet:

इन पेड़ों को क्या यारों पेड़ कहा जाए,

जो धूप की शिद्दत में भी छाया नहीं करते ।

Even in the heat of the summer, this Government is not ready to give its shade to other States. It is not ready to see all the States neutrally. Not only that, but also it has become a leafless tree,

कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते,

फिर कहां उनके साये हुए हैं ।

That is the position of this Government. The disability to look beyond one State in the North and another State in the South is the sign of a failed-governance, and also of utter unfairness. For example, many States are neglected and so is my State of Kerala.

Sir, I would urge the hon. Finance Minister to see what the hope Kerala had and what has been given to it. Kerala deserved everything. It expected and hoped for a little, but got nothing. That is our position. Kerala was neglected. Similarly, the minorities, backward communities, farmers, youths, women, and the middle-class did not get the due consideration, which they deserve. I would like to emphasize the point that this Budget is divisionary, diversionary and discriminatory. It is the divisionary policy, it is the discrimination, that leads to a kind of economic boycott.

The hon. Finance Minister referred to ?inclusion? several times. Once the hon. Finance Minister mentioned - विकास भी, विरासत भी । विरासत क्या है? Our heritage is the heritage of plurality. It is not of singular polarity. Even in the on-going *Kanwar Yatra*, the policy adopted by the rulers of those States was against the very spirit of our Constitution; it was against the *Virasat* that we have got. Even the Supreme Court had to intervene into the matter and issue a stay order to stop the States from implementing that directive which was asking to display the identity of the shopkeepers.

Sir, even the other day, one Head Constable, Ashik Ali jumped into the river to save a young *Kavwaria* named Monu Singh, a 21-year-old boy. Ashik Ali jumped courageously with a human spirit and selfless courage. This is our v*irasat*. This is our Indian society. But what is going on against this? This has to be checked. There are many such incidents. So, the *virasat* is a*mnoaman*, पयाम-ए-मोहब्बत । हम पयाम-ए-मोहब्बत आम करते ही रहेंगे against all the kinds of hatred and divisionary agenda.

Sir, let me talk about the minorities, the backward communities and the middle class. The Government thinks that the middle-class should be taxed, taxed and taxed. Actually, the middle-class should be considered as a powerful engine of growth.

Sir, what is the essential need of farmers today in the country? At the very outset, the hon. Finance Minister was mentioning about research. Research is good. We all appreciate it. But is research the preliminary need of the Indian farmers? The preliminary need of the farmers is the legal guarantee on MSP. In a country where youths share the largest part of the population, where millions of college-educated youths are there, job creation should be the primary agenda of that country.

At least one relief is there that the Government has started identifying that there is a problem of jobs in the country. With regard to women?s rights, I would say that there were schemes sanctioned for ensuring jobs for them, but even those schemes have been reduced.

Sir, the solution lies not in giving subsidies to the corporate sector, but in creating the demand. The sources of demand are private consumption, investment and export. So, these things have to be taken into consideration.

While concluding, I would like to request the hon. Finance Minister that there should be equal rights for all the States, including my State of Kerala. The Union Government should be neutral, and it should respect the principles of pluralism and federalism.

Thank you.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : सभापति जी, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 वीं बार एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है ।

सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 के बजट को सम्पूर्णता में देखने की आवश्यकता है । 1 फरवरी, 2024 को इस सदन में अंतरिम बजट पेश हुआ था, तब से अब तक 5 महीने से ज्यादा की अवधि गुजर चुकी है । बहुत सारी योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है । उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धनराशि का भी आवंटन किया जा चुका है ।

सभापति महोदय, यदि वर्ष 2014 से आज के बजट की तुलना करें तो पाते हैं कि बजट का आकार बढ़ा है, बजट का साइज बढ़ा है । इकोनॉमी फॉर्मल से इनफॉर्मल की ओर बढ़ी है । साथ ही साथ जीएसटी की शुरुआत हुई और टैक्स कलैक्शन में बढ़ोतरी हुई । यूपीए के समय में जो डायरेक्ट टैक्स कलैक्शन 6.38 लाख करोड़ रुपये था, वह वर्ष 2024 में बढ़कर 23.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है । यह टैक्स कलैक्शन यूं ही नहीं बढ़ा है । इसके लिए प्रोसीजरल रिफॉर्म हुआ है । आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वर्ष 2024-25 सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता के कल्याण के साथ-साथ उद्योगों और इंडस्ट्रीज को भी मजबूती प्रदान करने वाला है । इस बजट में मातृशक्ति के बढ़ने के लिए पूरा-पूरा खुला मैदान है । कृषि और किसानों की खुशहाली का भी आधार इस बजट में है । इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है और गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है । यह बजट भारत की ऊर्जा से ओत-प्रोत और रोजगार सृजन के प्रति समर्पित है । पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधान मंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था कायम की, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को उनके खाते में बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप के जितना पैसा जाना था, उतना पैसा पहुंचा है ।

पिछले 10 वर्षों में करीब-करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आये । पीएलआई स्कीम में ?मेक इन इंडिया? ने हमारे निर्यात को काफी आगे बढ़ाया है । निर्यात के क्षेत्र में देश लगातार रेकॉर्ड कायम कर रहा है । पिछले 10 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था फॉर्मल इकोनॉमी की ओर अग्रसर हुई है । डिजिटल इंडिया से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, बल्कि इसकी वैश्विक छाप भी पड़ी है ।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट की नौ प्राथमिकताएं हैं । उन प्राथमिकताओं को गिनाने की आवश्यकता नहीं है । सभी लोगों ने उन प्राथमिकताओं को देखा होगा, उन पर गौर किया होगा । अभी किसानों की बात हो रही थी । सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है, उस पर भी काफी चर्चा हो रही थी ।

महोदय, जलवायु परिवर्तन का पूरे विश्व भर में असर पड़ा है, खासकरके खेती पर इसका बेहद असर पड़ा है । पहली बार हमारी सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने की बात कही है । मेरा संसदीय क्षेत्र पलामू है, इसलिए इस बात की महत्ता को शायद और कोई उतना न समझे, जितना मुझे समझने का अवसर मिला है । मेरा क्षेत्र इन-शैडो एरिया में पड़ता है । वहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं के बराबर होती है । कभी वर्षा होती है, तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि फसल उगाना मुश्किल हो जाता है । यह जलवायु परिवर्तन का ही लक्षण है, जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है । ऐसे में, यदि सरकार के द्वारा, जो सरकार अपने को किसानों की हितैषी कहती है, उसके लिए काम करती है, इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से यह एक प्रशंसनीय कदम है । इसकी प्रशंसा होनी चाहिए ।

जलवायु के अनुकूल 109 किस्में उगाई जाएंगी और उनके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा । अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़े जाने का प्रावधान है । उसमें सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग का भी प्रावधान है । इसके साथ-साथ, पल्सेज और ऑयल सीड्स की उत्पादकता बढ़ाने, उनके भण्डार और उनके लिए बाज़ार की व्यवस्था की बात भी बजट में कही गई है । मुख्य कंज्यूमर सेंटर्स में वेजिटेबल क्लस्टर्स की स्थापना

की बात भी कही गई है । सिम्स के फार्मिंग के बारे में पहली बार बात की गई है । सिम्स की फार्मिंग के साथ-साथ, उनके प्रॉसेसिंग के लिए और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए भी इस बजट में बात कही गई है ।

इस बजट में एक नैशनल को-ऑपरेशन पॉलिसी बनाने की बात भी की गई है । इस साल एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए 1.59 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है ।

रोजगार सृजन और कौशल प्रशिक्षण के लिए भी कतिपय योजनाओं की चर्चा की गई है । फर्स्ट टाइमर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन के लिए और एम्प्लॉयर को भी इंसेंटिव देने की बात कही गई है । इसके अतिरिक्त, 20 लाख युवाओं को 5 वर्ष की अवधि में राज्य सरकारों एवं इंडस्ट्रीज की सहायता से कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा । एक हजार आईटीआईज़ को अपग्रेड किया जा जाएगा । इसके अलावा, एक करोड़ युवाओं को 500 टॉप कम्पनीज़ के साथ इंटर्नशिप करने की व्यवस्था की गई है । इस इनटर्नशिप के दौरान उन्हें पांच हजार रुपए का मासिक वेतन भी दिया जाएगा और छ: हजार रुपए भी एकमुश्त देने की बात कही गई है ।

कामगारों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की भी चर्चा की गई है । कार्य स्थल पर महिला होस्टल और शिशु-गृह बनाने की बात भी कही गई है । कौशल प्रशिक्षण के लिए 7.50 लाख रुपए के ऋण की सुविधा भी प्रदान करने की बात कही गई है । घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दस लाख रुपए के ऋण का भी प्रावधान किया गया है । इस वर्ष रोड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ।

सभापति महोदय, ?पूर्वोदय स्कीम? की जो चर्चा बजट में की गई है, उस पर बहुत सारे सदस्यों ने अपने-अपने ढंग से अपने विचार व्यक्त किए हैं । मैं झारखंड राज्य से आता हूं, जो पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था । बिहार के बारे में आपने सुना होगा, ?बीमारू राज्य? का शब्द ढूंढ़ा गया था कि जो बीमारू राज्य हैं, जिनमें बिहार है, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था और जिनमें उत्तर प्रदेश था । ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मुझे एक-मिनट का और समय दीजिए, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर देता हूं । उस समय बिहार के लोगों को कितनी पीड़ा होती थी, शायद इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता । उस समय भी बिहार की बीमारी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गई । उस समय बिहार के विकास के बारे में कोई बात नहीं कही गई । आज जब बिहार के विकास की बात कही जा रही है, तो दूसरे लोगों को क्यों पीड़ा हो रही है? वे तो उन्नत हैं, हम तो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा विवाद होने की आवश्यकता है । आप अपने राज्य के लिए जरूर मांग कर सकते हैं, आप मांग कीजिए, लेकिन यदि बिहार को कुछ मिला है, तो उसके लिए प्रतिवाद क्यों कर रहे हैं?

माननीय सभापति : श्री विष्णु दयाल राम जी, अब आप समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री विष्णु दयाल राम : सभापति महोदय, मुझे तो जम्मू और कश्मीर पर भी बोलना है । ?(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री विष्णु दयाल राम : अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद, यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक पुलिस अफसर था, जैसा कि आप जानते हैं । इसलिए, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं और आपसे मैंने एक मिनट का एक्स्ट्रा समय मांगा है ।

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता वहां के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना थी । उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी । जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी सरकार ने अपनाई । सुरक्षा उपायों को मजबूत किया । आतंकवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को बेअसर करने के लिए कार्यवाही की । युवाओं को आतंकवाद से दूर रखने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की कार्यवाही की और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया ।

सभापति महोदय, सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए भी मल्टी परपज़, multipronged स्ट्रैटिजी अडॉप्ट की गई । पत्थरबाजी और संगठित हड़ताल बिलकुल समाप्त हो गई । यदि आप आंकड़ों पर गौर करेंगे, तो वर्ष 2018 में 228 आतंकवादी घटनाएं हुईं, जबकि वर्ष 2023 में केवल 46 हुईं । मुठभेड़ की घटनाएं वर्ष 2018 में 189 हुईं, जबकि वर्ष 2023 में 48 हुईं । वर्ष 2018 में जितने सुरक्षा बल मारे गए, उनकी संख्या 91 थी और वर्ष 2023 में जो सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए, उनकी संख्या 30 थी । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री विष्णु दयाल राम : इन सुरक्षा के उपायों के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सबके सामने आए हैं । जन-जीवन सामान्य हो गया है, सभी स्कूल, अस्पताल और सेवाएं खुली हैं । कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है । जी 20 पर्यटन समूह की बैठक सफलतापूर्वक श्रीनगर में संपन्न हुई है । लाल चौक अब उत्सव का गवाह बन रहा है, अब वह लोगों से भरा पड़ा रहता है, जहां कभी लोग जाया नहीं करते थे । संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से एक और मतदान के साथ समाप्त हुए हैं ।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

15.00 hrs

SHRI BALWANT BASWANT WANKHEDE (AMRAVATI): Hon. Chairperson, thank you very much for giving me this opportunity to speak in this august House. I would also like to thank my Congress Party, MVA and people of my Amravati Constituency. Everybody in this House is asking whether this Budget is meant for the entire country or it is only for a few States.

This is quite visible too. The Chief Minister of Maharashtra Shri Eknath Shinde and Ajitdada Pawar have made a big sacrifice to secure power in the name of Mahayuti. But that sacrifice is completely ignored while preparing this Budget. Maharashtra is the largest contributor in GST collection, but we have received not a single penny. Our Finance Minister tried to show that this Budget is meant for the poor women,

farmers and youth but she lacks genuineness. She tried to paint a rosy picture but in vain. Our farmers have to suffer a lot and she is busy playing with the numbers. We regard farmers as ?Annadata? but this is a mockery indeed. Both the Union and the State Governments are playing with their emotions. This Government had promised to double the income of farmers to provide remunerative prices to their produces. But the farmers are still committing suicides in Maharashtra in large numbers. Around 557 farmers have committed suicide in Vidarbha region. In my constituency, 170 farmers committed suicide in the last six months because they are not fetching remunerative prices for the crops like cotton and soyabean. In the year 2014, he was getting around Rs. 10,000, but today he gets only Rs. 7,000 per quintal for cotton. For soyabean, earlier it was Rs. 6,000 but today it is only Rs. 4,000 per quintal. We lack the irrigation facilities too. The irrigation projects are still incomplete in Vidarbha region which were started during Dr. Manmohan Singh?s regime.

Sir, there are rampant cases of papers leak in Maharashtra too. The students keep on appearing for exams but nobody is ready to take the responsibility. The Union and the State Governments avoid to talk about the old pension scheme. OPS is much needed for the survival of pensioners? family.

Sir, around 30 per cent posts are vacant in the Health Department. Mother and child mortality rates are still very high in my Melghat region. These deaths should be stopped immediately.

महोदय, कारण यह है कि ये इमारतें, सड़कें, पुल बनाए हैं । क्या इनका जिक्र करते-करते ये अपने आपको भूल तो नहीं गए क्योंकि जो देहात है, उसका विकास होना चाहिए ।

Sir, if we want to develop infrastructure, it should be done in a proper and logical manner. Sir, I am also concerned about the budget deficit. We should work together for the overall development of our country. जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदुस्तान तेरा नाम रहेगा ।

The MSME sector contributes around 30 per cent to our GDP and also it provides employment to around 11 crore people. But unfortunately, there is no special provision for it in this Budget. This sector had to suffer a lot due to demonetization of 2016 and corona pandemic in 2020. On one hand, you are spreading education, but on the other hand you are shutting down the schools. I doubt our next generation would be illiterate possibly. Hence, I demand that sufficient funds should be allocated for the education sector too.

महोदय, दिनांक 25, जून 2075 को आपातकाल घोषित हुआ था । इसकी जानकारी आने वाली पीढ़ी को होनी चाहिए, यह बताने के लिए केंद्र सरकार ने 25 जून को ?संविधान हत्या दिन? मनाया । उसका नोटीफिकेशन भी निकला । गैजेट में दिया गया । मेरी राय है कि यह फैसला राष्ट्रीय हित में नहीं है । संविधान का हत्या दिवस, यह संकल्प, यह विचार असंवैधानिक है । यह नकारात्मक विचार है । क्या कभी हत्या का सैलिब्रेशन होता है? आप हत्या का सैलिब्रेशन मना रहे हैं । यह उचित नहीं है । इससे आपस में दरार पड़ेगी । संविधान अमर है और संविधान अमर रहेगा । बार-बार हमारे प्रधान मंत्री संविधान को माथा टेकते हैं । ... यह उचित नहीं है । यह जो दिन मनाया है, इसे वापस लेने के लिए मैं आज सरकार से विनती करता हूं ।

माननीय सभापति : आपने प्रधान मंत्री जी के लिए जो शब्द कहे हैं कि ... ** ये शब्द वापस लिए जाएं, रिकार्ड से हटा दिए जाएं ।

आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री बलवंत बसवंत वानखडे : सभापति जी, माननीय सदस्या बोल रही थीं । आज सरकार जो बेच रही है, वह कांग्रेस की देन है । जिस स्कूल में वे पढ़ी हैं या उनके परदादा जिस स्कूल में पढ़े हैं, वह कांग्रेस की देन है । बार-बार यह पूछते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल के शासन में क्या किया, यह उसका उत्तर है ।

सभापति जी, यह एससी, एसटी और बहुजन का बजट नहीं है । इस बजट में इन लोगों को बाहर रखा गया है, इसलिए मैं इस बजट की निंदा करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं । जय हिंद, जय महाराष्ट्र ।

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, वर्ष 2024-2025 के बजट पर आपकी ओर से बोलने का मौका मिला है और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से समय मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं ।

महोदय, एनडीए और भाजपा के कुछ सदस्य अभी बहुत कुछ बोल रहे थे, ?नाल मढ़ा रहे थे? कि हम किसानों के बहुत हितैषी हैं । दस सालों से केन्द्र में उनकी सरकार है और समस्या वहीं की वहीं पड़ी रह गयी है । युवा बेरोजगार है, पेपर्स लीक होते हैं और ये कहते हैं कि वे किसानों के हितैषी हैं । ये कैसे हितैषी हैं? इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है, गरीब, दलित, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है । सरकार की ओर से यह कहा गया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे । दस सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है । हमेशा यही होता है कि कुछ नहीं होता है । यह बजट ?सरकार बचाओ? बजट है । यह बजट किसानों के लिए गारंटी नहीं है । राज्य को चिह्नित कर बजट आवंटन किया जाता है ।

महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र सोनभद्र, राबर्ट्सगंज, चन्दौली के चकिया, नौगढ़ इत्यादि तमाम जगहों के जो ब्लॉक हैं, तहसील हैं, वहां पर कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां गरीबों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे अपने घर-दुआर, परिवार में रहकर आई.ए.एस., पी.सी.एस. बन सकें, दारोगा बन सकें, बी.डी.ओ. बन सकें । सभी लोग अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में यह सोचें कि आज़ादी के 76 सालों के बाद भी लोग किस परिस्थिति में जी रहे हैं ।

महोदय, किसानों की बात करने वाले क्या यह बताएंगे कि जिस जिले में बारिश नहीं हो रही है, वहां ?सूखा? घोषित करेंगे? कई जगहों पर बाढ़ आई हुई है, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र में सूखा पड़ा हुआ है । इतना ही नहीं, वहां पीने के पानी की भी बहुत परेशानी हो रही है ।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों को जैसे कोटा का राशन मिलता है, वैसे ही किसानों को अंगूठा लगवाकर लाइन में खड़ा कराया जाता है और तब भी उन्हें खाद, बीज नहीं मिल पाते हैं । उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और आप कहेंगे कि आप किसानों के हितैषी हैं । वह उन्हें इसलिए नहीं मिलता है कि वहां सर्वर डाउन रहता है । वहां 200-300 किसान उसके लिए अंगूठा लगाकर बैठे रहते हैं और उन्हें खाद नहीं मिल पाती है और इसके कारण वे रोपनी नहीं कर पाते हैं ।

सभापति महोदय, सोनभद्र, चन्दौली और अन्य जिलों में ?सूखा? घोषित कर किसानों से ऋण वसूली रोका जाए और कम ब्याज पर उन्हें पैसे देकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए । अपने को किसानों के हितैषी बताने वाले एनडीए गठबंधन के लोग क्या यह करेंगे? वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये लम्बी-लम्बी बातें करते हैं ।

अभी हमारे बिहार के ??? चाचा की पार्टी के ललन सिंह जी बोल रहे थे ।? (व्यवधान) हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार इसकी गारंटी तो दे दीजिए । आप गारंटी क्यों नहीं देते हैं?? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य ने जो ??*? शब्द यूज किया है, इसको हटा दिया जाए ।

श्री छोटेलाल : सभापति महोदय, मैंने एक शेर लिखा है । इसे अपने को किसानों के हितैषी बताने वाले एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान से सुनें -

जो मुफ्त शिक्षा, दवा मुफ्त देगा,

किसानों को एमएसपी गारंटी करेगा,

देगा समय से बिजली, खाद, पानी,

वही तो किसानों का नेता रहेगा,

वही तो किसानों का नेता रहेगा ।

महोदय, युवा बेरोजगार है, लाचार है, गरीब परेशान है । सभी लोग समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं । उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और अखिलेश भैया आने वाले हैं ।

महोदय, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा । जय समाजवादी पार्टी, जय अखिलेश, जय उत्तर प्रदेश ।

श्री राजेश रंजन (पूर्णिया): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं पहले कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा ।

वर्ल्ड इनइक्वेलिटी डेटाबेस के ताज़ा रिसर्च के मुताबिक भारत में असमानता अपने सौ सालों के शिखर पर पहुंच चुकी है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहते हैं कि भौतिक पूंजी पर ज़ोर देने के साथ-साथ मानवीय पूंजी के निर्माण पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, जिसको नहीं दिया गया । आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए ।

प्रथम फाउंडेशन की प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक 14 से 18 साल की उम्र वाले एक चौथाई बच्चे साधारण से लिखे हुए वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं, आज के इस हिन्दुस्तान में ।

कोविड-19 के बाद स्वास्थ और एजुकेशन पर सबसे ज्यादा यदि किसी को झटका लगा है तो वह बच्चों को लगा है ।

बहुत व्यापक स्तर पर मोदी सरकार अपनी पूर्ववर्ती यूपीए-2 से पीछे रह गई है । जीडीपी के हिस्से के रूप में लगभग छह प्रतिशत का घाटा हुआ है ।

मेक इन इंडिया में विफल होने का कारण राज्य के नेतृत्व वाले विकास मॉडल के बजाय सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर बहुत अधिक निर्भर करना है ।

आज की स्थिति में शेयरों को भी देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरों को भी लोगों के लिए खोला गया, जिसकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश 21,000 करोड़ रुपये थी ।

भारत के कार्यबल का 20 प्रतिशत ही औपचारिक रोज़गार से जुड़ा हुआ है । अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 में जहां देश के बेरोज़गारों में पढ़े-लिखे नौजवानों की तादाद 54.2 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2022 में बढ़ कर 65.7 प्रतिशत हो गई है ।

उसी तरह से ?मेक इन इंडिया? के माध्यम से भारत को दुनिया के सबसे बड़े कारखाने में तब्दील करने की बात थी, जिसमें 25 अरब डॉलर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों को भारत सरकार के द्वारा दिया गया ।

ये सब आंकड़े मेरे नहीं हैं, बल्कि भारत सरकार के हैं ।

लगभग 40 प्रतिशत श्रमिक कृषि क्षेत्र में काम करते हैं और केवल 20 प्रतिशत विनिर्माण नौकरियों या आईटी जैसी व्यावसायिक सेवाओं में काम करते हैं । यह जो 40 प्रतिशत मज़दूर है, दस सालों में इसके लिए कोई काम वर्तमान सरकार ने नहीं किया है । खास कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में जितनी नियोजित प्राइवेट नौकरियों की बात इस बजट में आई है, वर्तमान सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण को ले कर गंभीर नहीं है । जब आपने सरकारी नौकरी ही खत्म कर दी हैं, तो वहां भी आरक्षण नहीं रहेगा ।

बजट में ओबीसी वर्ग की राह में कठिनाई है । छात्रों की प्री-मीट्रिक स्कॉलरशिप 210 करोड़ रुपये, पोस्ट मीट्रिक स्कॉलरशिप लगभग 921 करोड़ रुपये है । नेशनल फेलोशिप 55 करोड़ रुपये, विदेशी शिक्षा की सब्सिडी स्कीम के लिए 25 करोड़ रुपये तथा छात्रावास योजना के लिए 45 करोड़ रुपये अनुमानित रखा गया है । मतलब वर्ष 2024 के बजट अनुमान में सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के विकास के लिए पैसा कम कर के बहुत घटा दिए हैं ।

एक तरफ आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी इकोनॉमी को भी खत्म कर रहे हैं । एससी, एसटी और ओबीसी के जो बच्चे विदेश जा रहे थे, उनके पैसे को आपने लगभग तीन हिस्से कम कर दिया । इसके बारे में मेरा कहना बिल्कुल साफ है ।

सभापति महोदय, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए । यह सबसे ज्यादा एजुकेशन, हेल्थ, मनरेगा और विडो पेंशन के बारे में है । विडो के बारे में जो पेंशन हैं, वह विधवा पेंशन है, वृद्धा

पेंशन है, निशक्त पेंशन है । मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आप कब तक उनको 300-400 रुपये देंगे? क्या इनका वृद्धा पेंशन एक हजार रुपया से दो हजार रुपये तक नहीं बढ़ना चाहिए । दूसरी चीज, मनरेगा जिस पर हमारे मजदूर निर्भर हैं, मनरेगा को आपने कितना कम बजट दिया है, इसको आप देख लीजिए ।

महोदय, जो हेल्थ सेक्टर है, ग्रामीण स्तर पर जैसे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट की समस्या है, जो संक्रमण की बीमारी है, इनके खर्च को ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग वहन नहीं कर सकते हैं । बजट में क्या इनके लिए ऐसी किसी योजना का प्रावधान किया गया है? आपकी आयुष्मान योजना असफल है । क्या आपने ऐसी कोई योजना बनाई है, जिसमें कैंसर, हार्ट की समस्या, ब्रेन ट्यूमर का इलाज फ्री हो सके । दवाई की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है । ग्रामीण स्तर पर किसी भी अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं है । वहां डॉक्टर नहीं हैं ।

महोदय, 67 प्रतिशत अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं । वहां टेक्निशियन और लैब की सुविधा नहीं है । सरकारी अस्पताल में कहीं भी दवाई नहीं दी जाती है । उनमें गुणवत्ता नहीं है । वहां कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है । इस पर आपने कुछ भी नहीं बोला ।

महोदय, अंत में, आपसे मेरा सिर्फ यही कहना है कि जाति जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है? इस पर आप कभी चर्चा नहीं करते हैं । जो दूसरी चीज है, वह ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में है । जेएनयू सहित जो बड़े-बड़े कॉलेजेज हैं, उनमें आरक्षण की क्या स्थिति है?? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, अब मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करूंगा । मैं कोसी, सीमांचल और पूर्णिया की बात करूंगा । मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पूर्णिया में आईआईटी, आईआईएम का हब बने । सीमांचल व पूर्णिया में केंद्रीय विश्वविद्यालय बने । सहरसा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बने ।

माननीय सभापति : राजेश रंजन जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं । पूर्णिया जंक्शन पर वाशिंग पिट बनने चाहिए । कोसी नदी पर हाई डैम बनने चाहिए । पूर्णिया को बिहार की उप राजधानी बनाना चाहिए । वहां उच्च न्यायालय के बेंच की स्थापना हो । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां मक्का और मखाना का सेंटर बने ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, बजट में फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रावधान होना चाहिए । मैं चाहूंगा कि मक्का और मखाना के लिए इस बजट में राशि का प्रावधान हो । बिहार को विशेष पैकेज देना चाहिए । वहां जितने भी बंद पड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी प्रावधान हो । सवा दो करोड़ मजदूर बाहर चले जाते हैं । इनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप 15 सेकेंड में अपनी बात पूरी कीजिए ।

श्री राजेश रंजन : सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि हमारे जो आंगनवाडी, रसोइया, ममता, आशा, नियोजित, संविदा और शिक्षा मित्र हैं, इनके लिए मेरा सबमिशन है । जैसे अभी अग्निवीर के बारे में सवाल उठ रहा है । उत्तर प्रदेश में जो नियोजित और संविदा पर शिक्षा मित्र हैं, उसमें देखा जाए तो टीचर के प्रति असमानता है । इसमें सम्मानजनक शिक्षा के प्रति असमानता है ।

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर) : सर, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं । आज हमारे प्रधानमंत्री जी कारगिल विजय दिवस के अवसर में लद्दाख में इंडियन आर्मी के साथ हैं । मैं देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद व प्रणाम करता हूं ।

जो बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने पेश किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । यह बजट किसान का है, यह बजट युवा का है, यह बजट एससी, एसटी का है । यह बजट पूरे देश के युवा वर्ग को आगे ले जाने के लिए है । इस बजट में स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये एलॉट किए गए हैं । स्पेस सैक्टर में 1 हजार करोड़ रुपये एलॉट किए गए हैं । मुद्रा लोन जो पहले 10 लाख रुपये था, उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक किया गया है । आदिवासी महिला, जिसके पास घर नहीं है, एससी, एसटी महिला, जिसके पास घर नहीं है, वह सोचती है कि देश के प्रधान मंत्री हमें घर देंगे, हम प्रधान मंत्री आवास योजना के घर में रहेंगे । यह सबसे बड़ी बात है । मैं अर्थ मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा बजट उन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए दिया है । 10 लाख करोड़ रुपये अर्बन हाउसिंग के लिए एलॉट किए गए हैं । आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि बिलो पावर्टी लाइन वालों की मदद करें, लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री जी की सोच है कि उन लोगों को भी सामने लेकर आना है और आज लेकर आए हैं ।

वुमेन डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं । हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है । सभी सोचते हैं कि जब बजट आएगा तो हमारे यहां ट्रेन चलेगी । मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं, रबीन्द्र नाथ के बंगाल से आता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंगाल से आता हूं । हम लोग भी बंगाल के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं । मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, पहली बार देश के प्रधान मंत्री और अर्थ मंत्री ने पूर्वोदय के लिए सोचा है और बंगाल, बिहार, ओडिशा सभी को डेवलप करने के लिए पूर्वोदय योजना को लागू किया है । किसी ने नहीं सोचा था कि ईस्टर्न जोन को आगे बढ़ना चाहिए । वेस्टर्न जोन तो हर टाइम आगे बढ़ता है लेकिन ईस्टर्न जोन आगे नहीं बढ़ता है । प्रधान मंत्री जी और अर्थ मंत्री जी की कृपा से इस बार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल बहुत आगे बढ़ रहे हैं । इस बजट में 89 हजार करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल के लिए एलॉट हुए हैं ।

मेरे तृणमूल कांग्रेस के सांसद मित्र कह रहे थे कि मोदी की गारंटी का क्या हुआ? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो काम हुआ है, वह काम आप लोग पहले करिए । जो प्रधान मंत्री आवास योजना में पैसे भेजते हैं, वे उसका नाम चेंज करके बंगाल आवास योजना कर देते हैं । जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का फंड भेजते हैं, उसका नाम चेंज करके बंगाल ग्राम सड़क योजना कर देते हैं । डेवलपमेंट होना चाहिए और हर सांसद सोचते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो । पश्चिम बंगाल, पूरे विश्व में जितने बनाना कंट्रीज़ हैं, पूरे विश्व में जितने रोहिंग्या हैं, उनको ये इनवाइट कर रहे हैं । इसमें हम लोग अच्छा रहेंगे, आप ही बताइए, नहीं रहेंगे । पश्चिम बंगाल में प्रति दिन 5,000 से 10,000 रोहिंग्या आ रहे हैं और आने के बाद पूरे भारत में सप्लाई हो रहे हैं । यह देश के लिए खतरा है । हमारे असम के चीफ मिनिस्टर ने भी बोला कि पश्चिम बंगाल को इसे देखना चाहिए । चीफ मिनिस्टर के भतीजे के लिए आप लोग सब छोड़ देंगे तो भारत का गणतंत्र कहां रहेगा? हम बोलेंगे कि देश में जितने रोहिंग्या आ रहे हैं, उनको वापस भेजना चाहिए । ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खतरे की बात है । पूरे विश्व का ठेका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ले लिया । वे बोल रही हैं कि जहां भी कोई डिस्टर्ब हो जाए, हमारे पश्चिम बंगाल में आ जाए, हम उसको जगह दे देंगे । आप यह बात कैसे बोल रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में जगह दे देंगे? हमारे यहां पर असेंबली में विरोधी दल के नेता पर अटैक हो रहा है । लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है । मेरा प्रधानमंत्री जी से विनती है, गृह मंत्री जी से विनती है, सांसद बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे । जो बड़ी-बड़ी बात बोल रहे थे, वह सबसे बड़ा चोर है । मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जितने भी फंड वेस्ट बंगाल में भेजेंगे, उसका पाई पाई का हिसाब होना चाहिए । वहां इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, इसको कोई देखने वाला नहीं

है । इन घोटालों के पीछे कौन है, इसे देखना चाहिए । पश्चिम बंगाल में हर दिन मर्डर हो रहा है, इसको देखने वाला कौन है? इसको देखना चाहिए । जितने सारा कुछ अभिषेक और बंदोपाध्याय बोले हैं ।

माननीय सभापति : सौमित्र जी, आप समाप्त कीजिए, एक मिनट में खत्म कीजिए ।

श्री सौमित्र खान : सर, दो मिनट टाइम दीजिए, ? (व्यवधान) पहले आप आइने में मुख देखिए । पश्चिम बंगाल के सीएम पूरे देश को खत्म कर देंगे । ? (व्यवधान) मुझे टाइम ही नहीं मिला । ? (व्यवधान) वहां का एक मिनिस्टर क्या बोल रहा है, हिन्दू सब काफिर है, एक मिनिस्टर बोल रहा है कि हम सब काफिर हैं? वहां पर बोल रहा है । जो हिन्दू है, सबको बाहर कर देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे । वर्ष 1990 कश्मीर में याद कीजिए, जैसे कश्मीर में हुआ था, पश्चिम बंगाल में वही होने वाला है । हम सभी से विनती करेंगे, आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी बनाकर पश्चिम बंगाल भेजिए क्योंकि पश्चिम बंगाल किसी की जागीर नहीं है । किसी एकला की जमीन नहीं है, हम लोगों को भी 39 परसेंट वोट मिला है । अभिषेक और बंदोपाध्याय क्या बोलेंगे, लिप्स एंड बाउंड्स कंपनी के 100 करोड़ रुपये ईडी ने अटैच किया है, उसका मालिक कौन है? इसका जवाब देना चाहिए । इस पर कोई डिबेट नहीं करता है । लेकिन नार्थ बंगाल में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है । रोहिंग्या ने मालदा, मुर्शिदाबाद, नार्थ परगना, साउथ परगना को खत्म कर दिया । हमारे रारह बंगाल में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो रोहिंगया आ रहा है । मैं अपनी डिमांड करके बात समाप्त कर दूंगा । बांकुड़ा, दुर्गापुर में रेलवे कोच के लिए रिक्वेस्ट किया है, वह काम हो जाए । विष्णुपुर में बांध का काम हो जाए, बाकुंडा रानीगंज रेल पथ बन जाए । तृणमूल कांग्रेस को भी बोलूंगा । एक सीनियर एमपी बार-बार बोल रहे थे, इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ... का इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि कितना घोटाला किया है । ... ने पांच हजार करोड़ रुपये का घोटाला किया है, इनको अरेस्ट करना चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूं । धन्यवाद ।

———